सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 03, नई दिल्ली । शनिवार, 16 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा।

03 राशन,आवास,पेंशन की राह आसान करेगा सरकार की यह योजना
06 हिमाचल में हलचल, हरियाणा में परिवर्तन
08 भारतीय नौसेना के लिए दूसरा 25टी बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया

भारत देश में कल चुनावों के ऐलान हो जाएगा और चुनावों की घोषणा के बाद देश में क्या-क्या बदल जाएगा? जानें

संजय बाटला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी शनिवार (16 मार्च) को बजेगी। चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आम चुनावों के साथ ही आयोग कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) राजीव कुमार आचार संहिता लागू होने की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि, आदर्श आचार संहिता का मतलब पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए बनाई गई गाइडलाइंस से है। चुनाव की घोषणा से लेकर प्रक्रिया पूरी होने यानी नतीजे जारी होने तक आचार संहिता लागू रहती है। संविधान में आदर्श आचार संहिता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता को प्रसिद्ध चुनाव आयुक्त टीएन शेषन द्वारा सख्ती से लागू किया गया था। एमसीसी के तहत कुछ नियम हैं जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना आवश्यक है। उल्लंघन की स्थिति में चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करता है।

क्या है आदर्श आचार संहिता?

आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। आदर्श आचार संहिता को आठ भागों में बांटा गया है। इसमें चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों के साथ-साथ विज्ञापन और आचरण से संबंधित दिशानिर्देश भी शामिल हैं। एमसीसी अपने आप में कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है लेकिन चुनाव आयोग को इसकी शक्तियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मिलती हैं। आदर्श आचार संहिता का भौगोलिक दायरा संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है।

आदर्श आचार संहिता के मुख्य नियम

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार एवम् राजनीतिक दलों और नेताओं पर लोकलुभावन घोषणाएं करने पर रोक लग जाती है। सरकार कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। जब तक एमसीसी प्रभावी है, कोई भी नई योजना लागू नहीं की जा सकती। मंत्रियों द्वारा चुनाव कार्य के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकार किसी भी तरह का वित्तीय अनुदान, सड़क या अन्य सुविधाओं का वादा, तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकती।

आप सब की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं की आदर्श आचार संहिता पहले से चल रहे किसी भी विकास कार्यों और योजनाओं पर रोक नहीं लगाती है। हां, लेकिन इन सभी विकास के कार्यों और योजनाओं को चुनावी प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक जरूर लग जायेगी।

राष्ट्रीय ट्रक आपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज दिनाक 16 मार्च 2024 को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक होली मंगल मिलन समारोह और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भांगड़ा ग्रुप, अमन जाजी, अजय हुड्डा और काजल हरियाणवी कलाकार, सन्नी अरोड़ा, अनिता और भावना शर्मा दिल्ली कलाकार के साथ खुशबू तिवारी भोजपुरी कलाकार जनता के बीच अपना जलवा दिखाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि समय पर पहुंच कर होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आनन्द प्राप्त करे।

आयोजक :- राष्ट्रीय ट्रक आपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन

गडकरी का धुबरी को तोहफा, 4-लेन गौरीपुर बाईपास के निर्माण के लिए 421.15 करोड़ की मंजूरी

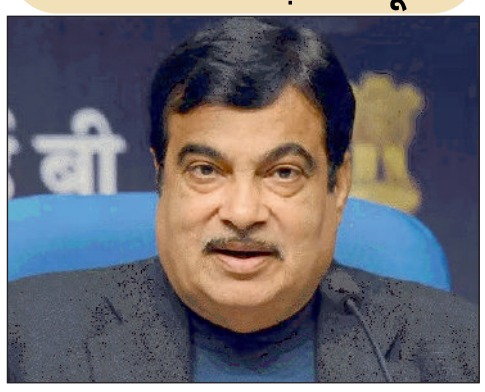

परिवहन विशेष न्यूज

असम में धुबरी के गौरीपुर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चुनावों से पहले एक प्रमुख पहल की घोषणा की है।

गौरीपुर दुमदीह गांव से बालदमारा तक नए चार-लेन नेशनल हाईवे 17 के निर्माण के लिए केंद्र ने 421.15 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है।

इस नए राजमार्ग के निर्माण में गौरीपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण बाईपास शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 9.61 किलोमीटर है।

इस बाईपास से गौरीपुर के निवासियों को राहत प्रदान करते हुए यातायात की भीड़ और सड़क दुर्घटनाओं जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को कम करने का अनुमान है।

विस्तृत सड़क सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, नया राजमार्ग गौरीपुर क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को काफी कम करने का लक्ष्य रखता है। जो स्थानीय आबादी की प्रमुख चिंताओं में से एक है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल के जरिए यह घोषणा करते हुए सरकार की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और पूरे देश में संपर्क बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

इस आवंटन की स्वीकृति, क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो गौरीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक सुरक्षित और सुगम आवागमन का वादा करता है।

देशभर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता: 22 महीने बाद दाम घटाए गए

नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे पहले 21 मई, 2022 (22 महीने) को दाम घटाए थे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी और पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे पहले 21 मई, 2022 (22 महीने) को दाम घटाए थे।

पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार (14 मार्च) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के परिवार का हित और सुविधा उनका लक्ष्य है।

केंद्र सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल-डीजल पर 2 प्रतिशत वैट कम किया था। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राज्य के हर जिले में पेट्रोल-डीजल कम से कम साढ़े 3 रुपए सस्ते होंगे। राजस्थान में अब 31.04 प्रतिशत की जगह 29.04 प्रतिशत वैट लगेगा।

21 मई 2022 में 8 रुपए प्रति लीटर कम हुआ था पेट्रोल

इससे पहले पेट्रोल-डीजल के दाम 2022 में घटे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। नए दाम 22 मई से लागू हुए थे। हालांकि, अभी जो दाम घटाए गए हैं उसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कम किए हैं। ये कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे दामों को रिवाइज करती हैं।

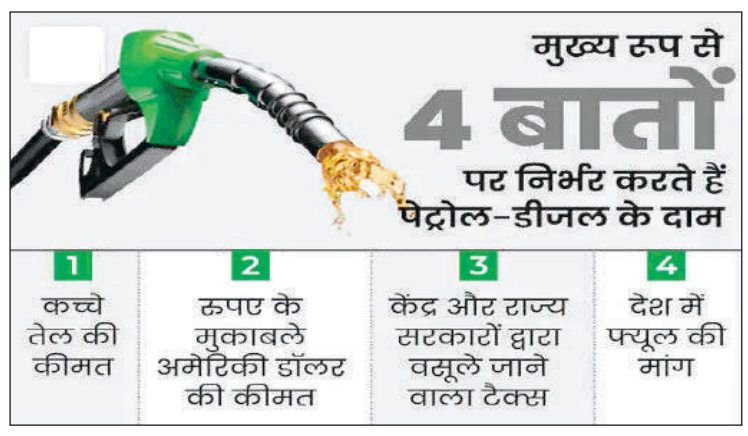

भारत में कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया।

अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर 2 प्रतिशत वैट कम किया

सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की दूसरी बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने वैट में 2 प्रतिशत कटौती की है। वहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी देशभर में 2 रुपए लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम कम कर दिए हैं। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राजस्थान के हर जिले में कम से कम साढ़े 3 रुपए पेट्रोल-डीज़ल पर जरूर कम होंगे। राजस्थान में अब 31.04 प्रतिशत की जगह 29.04 प्रतिशत वैट लगेगा।

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

	पेट्रोल (₹प्रति लीटर)		डीजल (₹ प्रति लीटर)	
शहर	अब	पहले	अब	पहले
दिल्ली	94.72	96.72	87.62	89.62
चंडीगढ़	94.24	96.20	82.40	84.26
जयपुर	104.88	108.48	90.36	93.72
रायपुर	100.39	102.45	93.33	95.44
मुंबई	104.21	106.31	92.15	94.27
भोपाल	106.47	108.65	91.84	93.90
कोलकाता	103.94	106.03	90.76	92.75
चेन्नई	100.75	102.63	92.34	94.24

सोर्स : IOCL

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने डीजल पेट्रोल की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर कम करने के लिए श्री नरेंदर मोदी, प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाये थे. इसलिए ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से मांग करी थी की पेट्रोलियम मंत्रालय से डीजल पेट्रोल के दाम कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर कम करवाये जाए. एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से एक और मांग की डीजल पेट्रोल के दाम हर साल में एक बार या ज्यादा से ज्यादा साल में दो बार ही तय किये जाए.

क्योकि हम सवारियों से पेहले से ही रेट तय कर लेते है और इधर डीजल- पेट्रोल के रेट बड़ा दिए जाते है. संजय सम्राट का कहना हें की हम काफी लम्बे समय से भारत सरकार से पेट्रोल डीजल और सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कह रहें हें और इसके लिए काफी पत्र भी भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी को लिखें हें .

संजय सम्राट का कहना हें की भारत में हर चीज के लिए जीएसटी लागू होता हें, भारत सरकार उसी तरह पेट्रोल डीजल और सीएनजी पर जीएसटी लगाकर भारत की जनता और भारत के ट्रांसपोर्टर्स को एक बड़ी सहूलियत दें सकती हें जिस से देश में पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा और विदेशो से करोडो की संख्या में विदेशी पर्यटक भारत में आएंगे क्योंकि डीजल की कीमते बड़े होने की वजह से देसी विदेशी पर्यटक ट्रैन से ज्यादा सफर करते हें. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी माँगा हें.

दिल्ली टेक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन

अगले साल से शुरू होगा दोनों नए कॉरिडोर का निर्माण, होंगी छह कोच; इस तकनीक का होगा इस्तेमाल

दिल्ली मेट्रो के फेज चार के दोनों स्वीकृति नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए लोकसभा चुनाव बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि अगले वर्ष इन दोनों कॉरिडोर का काम शुरू होगा। निर्माण पूरा होने पर इन दोनों कॉरिडोर पर छह कोच की मेट्रो चलेंगी। इन कॉरिडोर पर मजेंटा व पिंक लाइन की तरह चालक रहित स्वचालित मेट्रो का परिचालन हो सकता है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) फेज चार के दोनों स्वीकृति नए मेट्रो कॉरिडोर (लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ) के निर्माण के लिए लोकसभा चुनाव बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उम्मीद है कि अगले वर्ष इन दोनों कॉरिडोर का काम शुरू होगा। निर्माण पूरा होने पर इन दोनों कॉरिडोर पर छह कोच की मेट्रो चलेंगी। लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर पर मजेंटा व पिंक लाइन की तरह चालक रहित स्वचालित मेट्रो का परिचालन हो सकता है। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर मौजूदा ग्रीन लाइन (बहादुरगढ़-इंद्रलोक-कीर्ति नगर) कॉरिडोर की विस्तार परियोजना है। स्टैंडर्ड गेज के इस ग्रीन लाइन पर छह कोच के ही मेट्रो का परिचालन होता है। इसलिए इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर और इसके स्टेशन ग्रीन लाइन पर इस्तेमाल होने वाली तकनीक को ध्यान में रखकर डिजाइन होंगे।

पिंक व मजेंटा लाइन पर इस तकनीक का इस्तेमाल

लाजपत नगर-साकेत कॉरिडोर एक नई मेट्रो लाइन है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के सूत्रों के अनुसार इस कॉरिडोर पर अत्याधुनिक संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। मौजूदा समय में पिंक व मजेंटा लाइन पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा फेज चार में पहले से निर्माणाधीन गोल्डन लाइन (एरोसिटी-तुगलकाबाद) पर भी संचार आधारित ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए गोल्डन लाइन पर भी चालक रहित स्वचालित मेट्रो का परिचालन होना है।

लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक छोटा कॉरिडार

साकेत जी ब्लॉक गोल्डन लाइन और लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर का इंटरचेंज स्टेशन है। लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर 8.38 किलोमीटर का छोटा कॉरिडार होगा। ऐसे में इस कॉरिडोर की पहचान भी गोल्डन लाइन के रूप में हो सकती है। बताया जा रहा है कि डीएमआरसी इस पर विचार भी कर रहा है, लेकिन डीएमआरसी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है।

मान्यवर कांशीराम जन्म जयंती विशेष

"लेने वाले" समाज से "देने वाले" समाज में तब्दील करना चाहते थे कांशीराम

कांशीराम साहब ने "सोई हुई कौम" को जगाने में बहुत हद तक कामयाबी की

भारतीय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता कांशीराम साहब भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। इसके अन्त में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ और 1974 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और कांशीराम साहब ने अपने संघर्ष से वंचितों को फ़र्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन ख़ुद के लिए आरंभ से अंत तक 'शून्य' को प्रणाम करते रहे।

अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, 'फ़र्स्ट अमंग दि इक्वल्स' इसी शीर्षक से ब्रिटिश लेखक जेफ़री आर्चर ने 80 के दशक में ब्रिटेन की सियासत पर एक काल्पनिक उपन्यास भी लिखा था। इसका मतलब है किसी विशेष समूह में शामिल व्यक्तियों में किसी एक का ओहदा, प्रतिष्ठा, हैसियत आदि सबसे ऊपर होना। इसे देश की केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री के पद से समझा जा सकता है। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री ही होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की हैसियत बाक़ी सभी मंत्रियों से ज़्यादा होती है। उसके मुताबिक़ ही मंत्रिमंडल तय होता है वह इसका मुखिया है। दुनिया के लिए प्रधानमंत्री ही देश का चेहरा होता है। और यही वह पद है जिस पर आज़ादी के बाद दलित वर्ग का कोई व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा है। कांशीराम ने केवल एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया। ये व्यक्ति वे ख़ुद थे। घर त्यागने से पहले परिवार के लिए वे एक चिट्ठी छोड़ गए थे।इसमें उन्होंने लिखा था, 'अब कभी वापस नहीं लौटूंगा' और वे सच में नहीं लौटे न घर बसाया और न ही कोई संपत्ति बनाई। परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर भी वे घर नहीं गए। परिवार के लोग कभी लेने आए तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। संसार में ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व विरले ही हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से वंचितों को फ़र्श से अर्श तक पहुंचाया लेकिन ख़ुद के लिए आरंभ से अंत तक 'शून्य' को प्रणाम करते रहे।

कांशीराम ऐसी ही एक मिसाल हैं। वे संन्यासी नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन में कुछ त्यागने के प्रति जो समर्पण कांशीराम ने दिखाया, वैसा बड़े-बड़े संन्यासी भी नहीं कर पाते और न कभी कर पाएंगे। कई मानते हैं कि कांशीराम के नहीं होने का सबसे ज़्यादा दुख शायद उनके समय में बीएसपी से जुड़े उन कार्यकर्ताओं को होगा जो पार्टी छोड़ने या उससे निकाले जाने के बाद कहीं और नहीं गए। ये लोग कांशीराम का नाम नहीं लेते, आज भी उन्हें 'मान्यवर' या 'साहब' कहकर बुलाते हैं। ये लोग बीएसपी और कांशीराम के नाम पर राजनीतिक संघर्ष करने आए थे। आज न कांशीराम हैं और न ही मौजूदा बीएसपी वह बीएसपी है जो उनके समय हुआ करती थी।साहब, न सिर्फ दलित राजनीति बल्कि पूरी भारतीय राजनीति का व्याकरण बदल कर रख देने वाले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम का आज जन्मदिन है।

कांशीराम साहब की विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा का ही एक नया संस्करण है। हिंदी क्षेत्र में जो सियासी व्यवस्था और उसका संचालन है उन्होंने उसे बहुत गहराई से महसूस किया था और इसमें बदलाव का रास्ता निकाला था कि राज्य की सत्ता पर काबिज होकर जनता का विकास करना और इसके ज़रिए सामाजिक बदलाव लाना। कांशीराम आज होते तो दलित राजनीति का चेहरा भी कुछ ज्यादा सयाना हो सकता था। बहुजन समाज पार्टी ने सियासत में जो भी हासिल किया, उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे कांशीराम ने डीएस-4 के जरिए रखा था।

उनका जन्म 14 मार्च 1934 में पिर्थीपुर बुंगा ग्राम, खवसपुर, रूपनगर जिला, पंजाब भारत में हुआ था। मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में हुई थी। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के भाषण सुनते तो उनसे प्रेरित होकर मान्यवर कांशीराम अपने समाज की ओर अग्रसर हुए और फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने बसपा जैसी पार्टी का निर्माण किया। कांशीराम के जैसा कोई कद्दावर दलित नेता आज नहीं? कांशीराम साहेब भारत में सबसे पहले बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर ने दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत की, लेकिन जिस एक दलित नेता ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई लेकिन दलितों की सामाजिक स्थिति और उनके उत्थान को लेकर कांशीराम साहब की जो सोच थी आज के नेता उनके जैसा नज़रिया नहीं रखते, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ज़ीरो हैं। कुछ लोग बड़ी- बड़ी बातें बनाकर उनके नाम से अपनी-अपनी दुकानों पर सिर्फ़ उनके फोटो टांगकर सुगम व्यापार चला रहे हैं। आज आगरा नहीं पूरे विश्व में कांसीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह कई कार्यकर्मो का आयोजन कर उनको याद किया।

15 मार्च, 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक गांव खवासपुर में कांशीराम का जन्म हुआ था। वे जिस परिवार में पैदा हुए थे, वह पहले हिंदू धर्म की चमार जाति का परिवार था। लेकिन बाद में इस परिवार ने सिख धर्म को अपना लिया। उस दौर में पंजाब में हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों के कई परिवारों ने सिख धर्म अपनाया था। इसकी मूल वजह यह बताई जाती है कि जितना भेदभाव हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ होता था, उतना भेदभाव सिख धर्म में नहीं था।कांशीराम जिस परिवार में पैदा हुए थे, उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर ठीक-ठाक कहा जा सकता है। उनके पिता हरि सिंह के सभी भाई सेना में थे।हरि सिंह सेना में भर्ती नहीं हुए थे क्योंकि जो चार एकड़ की पैतृक जमीन परिवार के पास थी, उसकी देखभाल के लिए किसी पुरुष सदस्य का घर पर होना जरूरी था। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से कांशीराम को बचपन में उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। कांशीराम के दो भाई और चार बहनें थीं।इनमें से अकेले कांशीराम ने रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नात्तक तक की पढ़ाई पूरी की थी। 22 साल की उम्र में यानी 1956 में कठिन परिश्रम से कांशीराम को सरकारी नौकरी मिल गई।1958 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) में काम करना शुरू कर दिया। वे पुणे के पास डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला में सहायक के तौर पर काम करते थे। यहां आने के बाद उन्होंने देखा कि पिछड़ी जाति के लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव या उनका किस तरह से शोषण हो रहा है। कांशीराम के लिए यह स्तब्ध और दुखी कर देने वाला अनुभव था।यहीं से कांशीराम में एक ऐसी चेतना की शुरुआत हुई जिसने उन्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार के हित के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के बजाय एक बड़े मकसद के लिए काम करने वाला राजनेता बनने की दिशा में आगे बढ़ा दिया।

कांशीराम को अंबेडकर और उनके विचारों से परिचित कराने का काम दीना भाना साहब व डीके खपारडे ने किया। खपारडे भी डीआरडीओ में ही काम करते थे। वे जाति से महार थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। खपारडे ने ही कांशीराम को अंबेडकर की 'एनाहिलेशन ऑफ कास्ट' पढ़ने को दी। जिस रात कांशीराम को यह मिली, उस रात वे सोए नहीं और तीन बार इसे पढ़ डाला। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर की वह किताब भी पढ़ी जिसमें उन्होंने यह विस्तार से बताया है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अछूतों का कितना बुरा हाल किया है। कांशीराम ने बाद में कई मौकों पर माना कि इन दो किताबों का उन पर सबसे अधिक असर रहा। यहां से कांशीराम जिस रास्ते पर चल पड़े, उसमें सरकारी नौकरी ज्यादा दिनों तक चलनी नहीं थी। हालांकि, उनकी नौकरी छोड़ने के सही समय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दीना भाना साहब कहते हैं कि उन्होंने 1964 में नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की वजह के तौर पर यह बताया जाता है कि उन्होंने पिछड़ी जाति के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अबेडकर, बाल्मीकि और बुद्ध जयंती पर छुट्टी की मांग के लिए हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। कांशीराम ने 1971 में सरकारी नौकरी तब छोड़ी जब एक पिछड़ी जाति की महिला द्वारा सभी पात्रता पूरी किए जाने के बावजूद उसे नौकरी पर नहीं रखा गया।कहा जाता है कि कांशीराम ने उस अधिकारी के साथ मारपीट की जिसने उस महिला को नौकरी देने से मना किया। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि वे ताजिंदगी शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन पिछड़ों के उत्थान को समर्पित है। जिस दौर में कांशीराम दलितों के उत्थान के मकसद के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, उस दौर में देश का प्रमुख दलित संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। कांशीराम इससे जुड़े और जल्दी ही उनका इससे मोहभंग भी हुआ।14 अक्टूबर, 1971 कांशीराम ने अपना पहला संगठन बनाया। इसका नाम था - शिड्यूल कास्ट,शिड्यूल ट्राइब,अदर बैकवर्ड क्लासेज ऐंड माइनॉरिटी एंप्लॉइज वेल्फेयर एसोसिएशन। संगठन के नाम से साफ है कि कांशीराम इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को जोड़ना चाहते थे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि उनका लक्ष्य ज्यादा व्यापक था और वे शुरुआत में कोई ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते थे। जिससे उसे सरकार के कोपभाजन का शिकार होना पड़े।1973 आते-आते कांशीराम और उनके सहयोगियों की मेहनत के बूते यह संगठन महाराष्ट्र से फैलता हुआ दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया। इसी साल कांशी राम ने इस संगठन को एक राष्ट्रीय चरित्र देने का काम किया और इसका नाम हो गया ऑल इंडिया बैकवर्ड ऐंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंप्लॉइज फेडरेशन। यह संगठन बामसेफ के नाम से मशहूर हुआ। यह घोषणा देश की राजधानी दिल्ली में की गई। 80 के दशक की शुरुआत आते-आते यह संगठन काफी बढ़ा। उस वक्त बामसेफ ने दावा किया कि उसके 92 लाख सदस्य हैं जिनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और डॉक्टर भी शामिल हैं। कांशीराम ने 1981 में डीएस-4 की स्थापना की।डीएस-4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका मुख्य नारा था - हम एक सब हैं डीएस-4. यह एक राजनीतिक मंच नहीं था लेकिन इसके जरिए कांशीराम न सिर्फ दलितों को बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलबंदी करना चाह रहे थे। डीएस-4 के तहत कांशीराम ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला, जिसने सात राज्यों में तकरीबन 3,000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ विष वमन करने वाले नारों के जरिए जो जनसंपर्क अभियान कांशी राम चला रहे थे, उससे वह वर्ग उनके पीछे गोलबंद होने लगा जिसे साथ लाने के लिए कांशीराम ने डीएस-4 बनाया था। इसी सामाजिक पूंजी से उत्साहित होकर कांशीराम ने 14 अप्रैल, 1984 को एक राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बसपा ने सियासत में जो भी हासिल किया, उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे कांशीराम ने डीएस-4 के जरिए रखा था।

कांशीराम साहब को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में अगर वे खुद आगे आते हैं तो उनकी स्वीकार्यता बेहद व्यापक नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इस सूबे में बाहरी यानी पंजाबी के तौर पर देखा जाएगा। उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए वहीं का कोई दलित चेहरा चाहिए था। ऐसे में उन्होंने मायावती को चुना जो 3 जून, 1995 को प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनीं।भले ही बसपा की स्थापना को उस वक्त की मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी हो लेकिन देश के सियासी पटल पर कांशीराम के विचारों वाली बहुजन समाज पार्टी के उभार से राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। नौ अक्टूबर, 2006 को लंबी बीमारी के बाद कांशी राम का नई दिल्ली में निधन हो गया। कांशीराम की मौत के बाद उनकी विचारधारा के मुताबिक मायावती सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई तो लड़ रही हैं लेकिन सामाजिक बदलाव का काम उनसे छूटता जा रहा है। यानी आधा काम वो कर रही हैं बाकी का आधा काम दलित आंदोलन में लगे अन्य संगठनों को करना है। भारत में दलितों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है। दलितों की स्थिति में इतना परिवर्तन जरूर आया है कि एक मध्यमवर्ग विकसित हो गया है। सत्ता, प्रजातंत्र के जो फ़ायदे हैं वो दलितों के एक वर्ग तक पहुंचा है और वो शक्तिमान हुआ है लेकिन ज़्यादातर दलितों का एक बड़ा भाग अभी भी पिछड़ा और दमित है, उनका सशक्तिकरण होने की जरूरत है। इसके उलट कुछ जानकार यह कहते हैं कि आज कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती हैं, कोई दूसरा दलित नेता उनका नाम लेने से भी कतराता है। बहुजन समाज पार्टी, मायावती, कांशीराम, अंबेडकर बहुजनवाद की संरचना कांशीराम ने बहुजनवाद की संरचना की, उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर जो युग्म बनाया वो भारतीय राजनीति के लिए एक नवीन प्रयोग था। उन्होंने दूसरे वंचित समाज को बताया कि आपका वोट प्रतिशत 85 फ़ीसदी है और 15 फ़ीसदी वाले राज कर रहे हैं। तो यह एक नवीन प्रयोग था। नवीन नारे थे। और लोगों को आंदोलित करने की एक नवीन प्रक्रिया थी। एक कैडर था। आरएसएस और लेफ्ट पार्टी की तरह उन्होंने बहुजन, दलित आंदोलन में कैडर परम्परा की शुरुआत की। वो कैडर, वो बामसेफ़ अभी मरा नहीं है। लगातार वो अंबेडकरवाद की लकीर खींचे हुए है, और यूपी उपचुनाव में जीत एक बड़ा संदेश है कि अगर आज कोई वर्तमान ताकत से लड़ सकता है तो वो यही कैडर है। यह कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बहुजन विचारधारा वही है, आंदोलन वही है, लेकिन अगर आप राजनीति को देखेंगे तो कांशीराम कहा करते थे कि

'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी',

एक प्रजातांत्रिक राजनीति के तहत सभी समाजों के वर्गों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वही मायावती कर रही हैं। जब वो पिछड़े वर्ग या मुस्लिमों को टिकट देती हैं तो कोई नहीं बोलता लेकिन ब्राह्मणों को टिकट दे दें तो सब को यह ब्राह्मणवाद लगता है। जबकि यह 'जितनी संख्या, उतनी हिस्सेदारी' की अवधारणा के अनुसार है। बाहर बैठे कुछ राजनीतिक पंडितों की भाषाशैली कहीं न कहीं बहुजन समाज के पक्ष की नहीं विपक्ष के जैसी होती है। किस प्रकार वो खोट निकालें, उसे कैसे खंडित करें, उसे नकारात्मक कैसे दिखाएं यह उनकी भाषाशैली में दिखता है। यही कारण है कि मायावती आज कांशीराम की दिखाये रस्ते पर नहीं चल रही हैं ऐसा दिखाई पड़ता है।वो मायावती की दूरदर्शिता की तारीफ में कहते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दूरदर्शिता के अंतर्गत बहनजी ने अपने मतदाताओं को केवल यह कहा है कि आप पार्टी को वोट ट्रांसफर कर दीजिए। यह अपने आप में भारतीय राजनीति की पराकाष्ठा कही जाएगी जिसमें केवल इशारों के साथ साथ 100 फ़ीसदी वोट ट्रांसफर होते हैं। क्या भारत में कोई राजनीतिक दल ऐसा दावा कर सकता है ?ऱआज कुछ दलित हिंसा की राजनीति में भी शामिल हो रहे हैं। वो कहते हैं, ऱकांशीराम अतिवाद का विरोध करते थे। वो कभी भी उग्रवादी चेतना से लैस नहीं थे। दलितों से कहते थे कि हिंसा के रस्ते पर मत जाओ, लेकिन आज कुछ दलित हिंसा के रस्ते पर भी जाते हैं जो कांशीराम की विचारधारा नहीं थी।ऱमायावती के सिवा आज का कोई भी दलित नेता लेकर नहीं चल रहा है। यहां तक आज के दलित नेता उनका नाम लेने से भी परहेज करते हैं। अगर कांशीराम को सचमुच मान कर चल रहे होते तो उन्हें भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे होते। जिन्होंने भारतीय राजनीति को बदला उन्हें क्या भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए था। अगर किसी ने इसकी मांग की है तो वो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने की। दूसरे लोग कांशीराम की विचारधारा या उनके बताए मार्ग पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं।

कांशीराम ने पार्टी के गठन के साथ 'बहुजन समाज' का एक पुख़्ता आधार तैयार किया। वे देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूमकर 1984 से लगातार केवल पिछड़े, दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के बीच अभियान चलाते रहे। 1991 में इटावा से उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी राजनीति में नया समीकरण आरम्भ हो गया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के इरादे से मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। बहुजन के हित को देखने के लिए मुलायम सिंह और कांशीराम के बीच जिस तरह का सुलह हुआ था। तब कांशीराम ने दलितों के हितों से कोई समझौता नहीं किया था।गठबंधन भी इसी को लेकर टूटा था। उसमें एक गहरा सामाजिक कारण था। अभी मायावती जी ने भी उसी फॉर्मूले के तहत गठबंधन किया था। सामाजिक स्तर पर जो विरोधाभास है उसे सुलझाना होगा। यह एक कठिन काम है।

दलितों के उत्थान को लेकर कांशीराम की सोच थी कि उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। वो इन्हें 'लेने वाले' समाज से 'देने वाले' समाज में तब्दील करना चाहते थे और उन्होंने एक सोई हुई कौम को जगाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल भी की। बहुजन समाज पार्टी जीत से बसपा में ऊर्जा का संचार हुआ। भारतीय राजनीति में जीत और हार व्यक्ति की प्रसिद्धि की निशानी हो सकती हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं। जिनको जीत और हार से डिगाया नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी भी आंदोलन के मूड में हैं। उनका लगातार वोट प्रतिशत बना रहता है।लेकिन कुछ सवारी करने वाले लोग आ जाते हैं, इसलिए ये कभी कभी बढ़ा हुआ दिखता है, जो पार्टी के नहीं होते हैं वो दिखावे में विश्वास करते हैं। जो दल के भीतर हैं उनको अपने दल का ठहराव पता होता है। हर चुनाव के बाद मायावती और उनकी पार्टी को खत्म बता दिया जाता है लेकिन अगले चुनाव में वो उसी सिद्दत के साथ एक बार फिर सामने दिखाई देती हैं। जो लोग डर और थकने की वजह से बैठ गए थे उनमें गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में मिली जीत से ऊर्जा का संचार हुआ है।

कांशीराम साहब को पूरी तरह समझने में चूक गए थे अटल जी

ऊपर जो छोटी सी सब हेडिंग है, उसका कांशीराम के जीवन की एक घटना और उद्देश्य दोनों से गहरा संबंध है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांशीराम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया।उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' का नारा देने वाले कांशीराम सत्ता को दलित की चौखट तक लाना चाहते थे।वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। यह क़िस्सा पहले भी बताया जाता रहा है, लेकिन इस पर खास चर्चा नहीं हुई कि आख़िर अटल बिहारी वाजपेयी जी कांशीराम साहब को राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते थे। कहते हैं कि राजनीति में प्रतिद्वंद्वी को प्रसन्न करना उसे कमज़ोर करने का एक प्रयास होता है। ज़ाहिर है वाजपेयी जी इसमें कुशल होंगे ही लेकिन जानकारों के मुताबिक वे कांशीराम साहब को पूरी तरह समझने में थोड़ा चूक गए। वरना वे निश्चित ही उन्हें ऐसा प्रस्ताव नहीं देते।वाजपेयी के प्रस्ताव पर कांशीराम की इसी अस्वीकृति में उनके जीवन का लक्ष्य भी देखा जा सकता है। यह लक्ष्य था सदियों से ग़ुलाम दलित समाज को सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठाना। उसे 'फ़र्स्ट अमंग दि इक्वल्स' बनाना। मायावती के रूप में उन्होंने एक लिहाज से ऐसा कर भी दिखाया। कांशीराम साहब पर आरोप लगे कि इसके लिए उन्होंने किसी से गठबंधन से वफ़ादारी नहीं निभाई, उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से समझौता किया और फिर ख़ुद ही तोड़ भी दिया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कांशीराम ने इन सबसे केवल समझौता किया, गठबंधन उन्होंने अपने लक्ष्य से किया। इसके लिए कांशीराम के आलोचक उनकी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन कांशीराम ने इन आरोपों का जवाब बहुत पहले एक इंटरव्यू में दे दिया था। उन्होंने कहा था, 'मैं उन्हें (राजनीतिक दलों) ख़ुश करने के लिए ये सब (राजनीतिक संघर्ष) नहीं कर रहा हूं। अपने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के दौरान कांशीराम ने, उनके मुताबिक़ पाखण्ड और अंधविश्वास से प्रभावित या उससे जुड़ी हर चीज़ का बेहद तीखे शब्दों में विरोध किया, फिर चाहे वे गांधी हों, राजनीतिक दल, मीडिया या फिर ख़ुद दलित समाज के वे लोग जिन्हें कांशीराम 'चमचा' कहते थे। उनके मुताबिक ये 'चमचे' वे दलित नेता थे जो दलितों के 'स्वतंत्रता संघर्ष' में दलित संगठनों का साथ देने के बजाय पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दलों में मौक़े तलाशते रहे। कांशीराम और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि इन जैसे नेताओं ने दलित संघर्ष को कमज़ोर करने का काम कामयाबी से किया। अपनी किताब 'चमचा युग' में कांशीराम ने इसके लिए गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि....अंबेडकर की दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को गांधीजी ने दबाव की राजनीति से पूरा नहीं होने नहीं दिया और पूना पैक्ट के फलस्वरूप आगे चलकर संयुक्त निर्वाचक मंडलों में उनके 'चमचे' खड़े हो गए।

कांशीराम साहब का मानना था कि जब-जब कोई दलित संघर्ष पाखण्ड को अभूतपूर्व चुनौती देते हुए सामने आता है, तब-तब अंधविश्वास वर्चस्व वाले राजनीतिक दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, उनके दलित नेताओं को सामने लाकर आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करते हैं। कांशीराम ने लिखा है....'औज़ार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे, खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई ख़तरा नहीं होता तो चमचों की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मांग नहीं होती। प्रारंभ में उनकी उपेक्षा की गई किंतु बाद में जब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व सशक्त और प्रबल हो गया तो उनकी उपेक्षा नहीं की सजा सकी। इस मुक़ाम पर आकर, ऊंची जाति के हिंदुओं को यह ज़रूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के ख़िलाफ़ चमचे खड़े करें।

1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद कांशीराम ने पुणे स्थित डीआरडीओ में बतौर सहायक वैज्ञानिक काम किया था। इसी दौरान अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर किए गए संघर्ष से उनका मन ऐसा पलटा कि कुछ साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर ख़ुद को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। अपने सहकर्मी दिनाभाना साहब व डीके खरपडे के साथ मिलकर उन्होंने नौकरियों में लगे अनुसूचित जातियों -जनजातियों, पिछड़े वर्ग और धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के साथ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंप्लायीज फेडरेशन (बामसेफ़) की स्थापना की। यह संगठन आज भी सक्रिय है और देशभर में दलित जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। 1981 में कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की शुरुआत की जिसे डीएस4 के नाम से जाना जाता है, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) का गठन किया।आगे चलकर उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा देश के किसी भी सूबे में पहली बार हुआ था।इस पूरे सफ़र में कांशीराम ने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा. इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर साइकल दौड़ाई और मीलों पैदल चले। ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने फटी कमीज़ पहनकर भी दलितों की अगुवाई की। उन्हें नीली या सफ़ेद कमीज़ के अलावा शायद ही किसी और रंग के कपड़े में देखा गया हो। 90 के दशक के मध्य तक कांशीराम की हालत बिगड़ने लगी थी। उन्हें शुगर के साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी।1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लगातार ख़राब होती सेहत ने 2004 तक आते-आते उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया। आख़िरकार नौ अक्टूबर, 2006 को दिल का दौरा पड़ने से दलितों की राजनीतिक चेतना का मानवीय स्वरूप कहे जाने वाले दिग्गज अपने विचार छोड़ कर पांच तत्व में विलीन हो गए।

> "दलितों के उत्थान को लेकर कांशीराम की सोच थी कि उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। वो इन्हें 'लेने वाले' समाज से 'देने वाले' समाज में तब्दील करना चाहते थे और उन्होंने एक सोई हुई कौम को जगाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल भी की। बहुजन समाज पार्टी जीत से बसपा में ऊर्जा का संचार हुआ। भारतीय राजनीति में जीत और हार व्यक्ति की प्रसिद्धि की निशानी हो सकती हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं। जिनको जीत और हार से डिगाया नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी भी आंदोलन के मूड में हैं। उनका लगातार वोट प्रतिशत बना रहता है।लेकिन कुछ सवारी करने वाले लोग आ जाते हैं, इसलिए ये कभी कभी बढ़ा हुआ दिखता है, जो पार्टी के नहीं होते हैं वो दिखावे में विश्वास करते हैं।

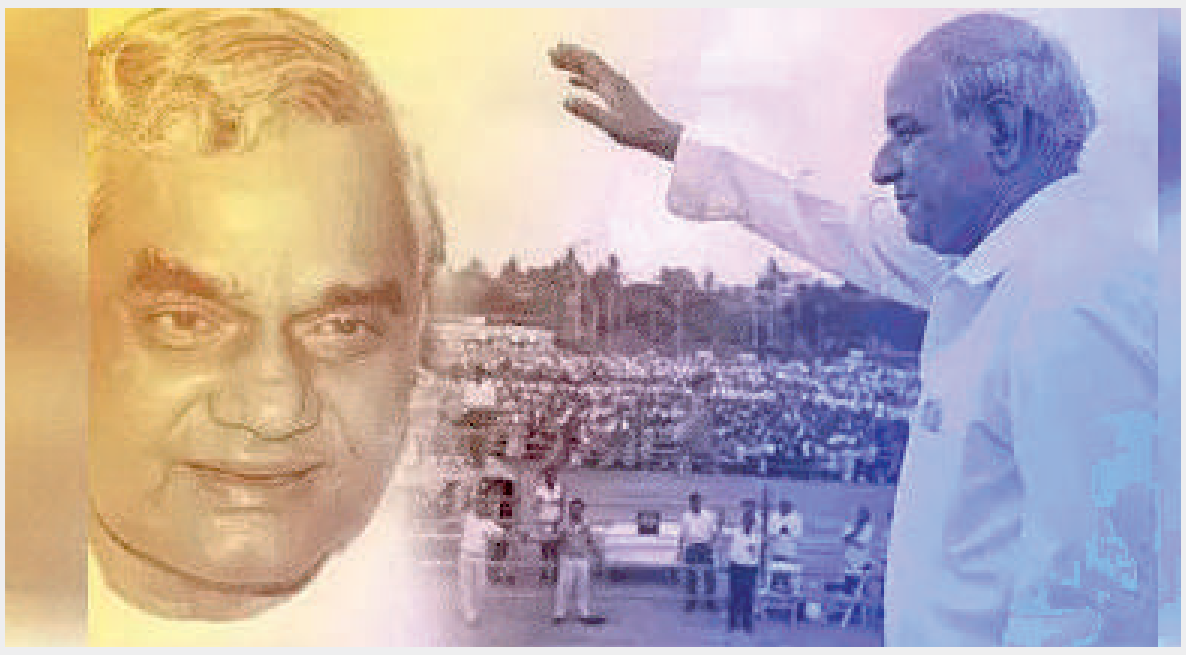

राशन,आवास,पेंशन की राह आसान करेगा सरकार की यह योजना,जानें कैसे मिलेगी आम आदमी को मदद

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करती है. विगत दिवस 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है. जिससे आमजन को ढेरों फायदे होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद बिना किसी झंझट के राशन, आवास, पेंशन पा सकेंगे. यही नहीं विगत दिवस पीएम मोदी ने करीब एक लाख पात्र लोगों को ऋण राशि भी वितरित की गई. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल से लोगों को काफी फायदा होने वाला है. आइये जानते हैं आमजन के लिए कैसे उपयोगी है पीएम सूरज पोर्टल, आखिर पीएम सूरज पोर्टल है क्या?

अभी तक लोगों को कंफ्यूजन है कि पीएम सूरज पोर्टल है क्या. आपको बता दें कि पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है. जिसे सामाजिक उत्थान और रोजगार के लिए डिजाइन किया गया है. इस पोर्टल के जरिए जरूरतमंदों को ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी. यही नहीं इसके माध्यम से ही आप 15 लाख तक के बिजनेस लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यानि पीएम सूरज पोर्टल आने से जरूरतमंदों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. पोर्टल पर ही आवेदन होगा. साथ ही वहीं आपके लोन को अप्रुवल भी मिल जाएगा. इसलिए आपको किसी भी बिचोलिये के चक्कर में ही पड़ने की जरूरत नहीं होगी.

जरूरतमंद कैसे लेंगे लाभ पीएम सूरज पोर्टल को वर्तमान युग में मील का पत्थर बताया जा रहा है. इसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना और सशक्तिकरण बताया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत ऋण तो मुहैया कराया ही जाएगा. इसके अलावा पीएम सूरज पोर्टल के जरिए व्यवसाय के नए अवसर भी तैयार होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस पीएम सूरज पोर्टल के जरिए वंचित वर्गों को लाभ मिल सकेगा. ज्यादा जानकारी के लिए पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है.राशन,आवास,पेंशन की राह आसान करेगा सरकार की यह योजना,जानें कैसे मिलेगी आम आदमी को मदद

केन्द्र सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करती है. विगत दिवस 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है. जिससे आमजन को ढेरों फायदे होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद बिना किसी झंझट के राशन, आवास, पेंशन पा सकेंगे. यही नहीं विगत दिवस पीएम मोदी ने करीब एक लाख पात्र लोगों को ऋण राशि भी वितरित की गई. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल से लोगों को काफी फायदा होने वाला है. आइये जानते हैं आमजन के लिए कैसे उपयोगी है पीएम सूरज पोर्टल, आखिर पीएम सूरज पोर्टल है क्या?

अभी तक लोगों को कंफ्यूजन है कि पीएम सूरज पोर्टल है क्या. आपको बता दें कि पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है. जिसे सामाजिक उत्थान और रोजगार के लिए डिजाइन किया गया है. इस पोर्टल के जरिए जरूरतमंदों को ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी. यही नहीं इसके माध्यम से ही आप 15 लाख तक के बिजनेस लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यानि पीएम सूरज पोर्टल आने से जरूरतमंदों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. पोर्टल पर ही आवेदन होगा. साथ ही वहीं आपके लोन को अप्रुवल भी मिल जाएगा. इसलिए आपको किसी भी बिचोलिये के चक्कर में ही पड़ने की जरूरत नहीं होगी.

जरूरतमंद कैसे लेंगे लाभ पीएम सूरज पोर्टल को वर्तमान युग में मील का पत्थर बताया जा रहा है. इसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना और सशक्तिकरण बताया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत ऋण तो मुहैया कराया ही जाएगा. इसके अलावा पीएम सूरज पोर्टल के जरिए व्यवसाय के नए अवसर भी तैयार होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस पीएम सूरज पोर्टल के जरिए वंचित वर्गों को लाभ मिल सकेगा. ज्यादा जानकारी के लिए पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर ठोका जुर्माना,मातृत्व मामले में गलत अपील पर झटका

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत अपील दायर करने पर केजरीवाल सरकार पर 50000 रूपये जुर्माना लगाया है।

राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग में कांट्रैक्ट कर्मचारी महिला स्टेनोग्राफर को मातृत्व लाभ देने के सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील खारिज करने के बाद यह जुर्माना ठोका है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 12 मार्च को अपने फैसले में कहा ,गलत मानी जा रही अपील को सभी लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है।साथ ही प्रतिवादी को आज से 4 सप्ताह के भीतर 50000 रूपये का भुगतान किया जाएगा।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शैलेंद्र कौर की बेंच ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपील गलत है।क्योंकि एकल न्यायाधीश के आदेश ने एक युवा महिला को दिया जिसने 5 साल तक दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में अत्यंत समर्पण के साथ सेवा की थी।बेंच ने अपने इस आदेश में आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया, जिसमें दिल्ली में सभी व्यस्क महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रूपये दिए जाएगें।हाईकोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि जो सरकार महिलाओ के हित को बढावा देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली ऐसी गलत अपील दायर की।अदालत ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार हुए कहा कि हमें विवादित आदेश में हस्ताक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

क्योंकि यह अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 26 सप्ताह के वेतन और अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देता है। उसने मातृत्व लाभ की मांग की थी।आप सरकार ने 6 अक्टूबर, 2023 के सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रूख किया था।जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के मुताबिक उसकी गर्भावस्था के कारण 26 सप्ताह के लिए मातृत्व और चिकित्सा लाभ दिया गया था। हालांकि आयोग ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उन्हें सूचित नहीं किया कि चूंकि उसका कांट्रैक्ट 31 मार्ग, 2018 को खत्म होने वाला था।इसलिए उसे कोई मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा।

मैट्रो के बिजली ट्रांसफार्मर को तेलीबाडे की दुकानों के समीप लगाने पर व्यापारियों में रोष, हादसे को न्योता

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। अति कंजेस्टेड और भीडभाड वाले तेलीबाडे चौंक व दुकानों से सटे क्षेत्र में मैट्रो के बिजली ट्रांसफार्मर को स्थापित किए जाने पर व्यापारियों,दुकानदारों, में दहशत का माहौल है। किसी बडे हादसे को न्योता देने वाली मैट्रो की योजना के लिए चुने गए इस स्थान को लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपना रोष जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ,समेत अन्य पदाधिकारियों में प्रेसीडेंट राकेश यादव ,संरक्षक प्रकाश महेंद्रू उपाध्यक्ष दीपक मित्तल, जनरल सेकेट्री राजेश शर्मा, कमल कुमार सहित सैंकडों व्यापारियों ने रोष जताकर दुख प्रकट किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि मैट्रो वैसे तो सुरक्षा व अपने सुथरे कार्य के लिए जानी जाती है ।लेकिन वह अति भीडभाड वाले क्षेत्र सदर बाजार तेलीबाडे में बेहद ही लापरवाही से कार्य कर रही है। हैवी ड्यूटी बिजली ट्रांसफार्मर बिल्कुल दुकानदारों के साथ लगाने से यहां भविष्य में जान-माल का नुकसान हो सकता है। यहां संकरी गलियों और भीडभाड के अलावा एक-दूसरे से सटी बिल्डिंग कभी भी बडी दुर्घटना का रूप ले सकती है। जबकि तेलीबाडा चौंक के बीच में पूरी जगह खाली है। यहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है। इस बावत पम्मा ने कहा कि वह मैट्रो के संबधित अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं। फिर भी इसके बावजूद दुकानों के समीप ट्रांसफार्मर लगाया गया तो व्यापारी सडकों पर उतरने पर मजबूर होंगे।

कौन हैं शीना रानी, जिनके नेतृत्व में अग्नि-5 का हुआ सफल परीक्षण

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत ने 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत अग्नि-5 मिसाइल का सोमवार (11 मार्च 2024) को सफल परीक्षण किया। लगभग 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली यह अंतर-महाद्वीपीय मिसाइल 'मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल' (एम.आई.आर.वी.) टेक्नोलॉजी के साथ देश में विकसित की गई। इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की वैज्ञानिक शीना रानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को डीआरडीओ की महिला वैज्ञानिक शीना रानी ने लीड किया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक शीना रानी की सफलता को देखते हुए को लोगों ने उन्हें 'दिव्य पुत्री' नाम दिया है। हैदराबाद के डीआरडीओ की हाईटेक लैब में कार्यरत 57 वर्षीय शीना रानी के काम के प्रति लगन और उत्साह के कारण उनके सहकर्मी उन्हें 'पावरहाउस ऑफ एनर्जी' के नाम से भी बुलाते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली शीना रानी 'अग्नि पुत्री' के नाम से प्रसिद्ध मशहूर मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस के नक्श-ए-कदम पर चलती हैं। टेसी थॉमस ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब शीना रानी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। शीना भारत के 'मिसाइल मैन' कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श मानती हैं।

शीना रानी का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। जब वह 10वीं कक्षा में थीं तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी माँ ने उनका पालन-पोषण किया। शीना रानी का कहना है कि माँ ही उनकी और उनकी बहन के जीवन की स्तंभ हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। उन्हें कंप्यूटर विज्ञान में भी विशेषज्ञता हासिल है। शीना रानी ने भारत की अग्रणी नागरिक रॉकेटरी प्रयोगशाला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में आठ वर्षों तक काम किया। साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद वह डीआरडीओ से जुड़ी थीं। साल 1999 से वह अग्नि मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। एमआईआरवी तकनीक वाली अग्नि-5 मिसाइल के विकास में शीना रानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शीना रानी का कहना है, "मैं डीआरडीओ की एक प्राउड मेंबर हूँ, जो भारत की रक्षा में मदद करती है।" उनके पति पी.एस.आर.एस. शास्त्री ने भी मिसाइलों पर डीआरडीओ में उनके साथ काम किया है। साल 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए कौटिल्य उपग्रह के प्रभारी भी थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन, पूर्व डीआरडीओ प्रमुख और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा मिली थी। दरअसल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपना करियर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से ही शुरू किया था। इसके बाद वह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए डीआरडीओ में शामिल हुए थे। इस दौरान शीना रानी और उनके पति को डॉक्टर कलाम के साथ काम करने का मौका मिला था। बताते चलें कि एमआईआरवी तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही है। इस मिसाइल को जमीन से या समुद्र से या फिर पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। एमआईआरवी तकनीक की खास बात ये है कि इसकी मदद से कई हथियार ले जाए जा सकते हैं और अलग-अलग स्पीड और अलग-अलग दिशाओं में इन हथियारों से टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है।

अब ये हालात है कि सीबीआई के द्वारा रंगे हाथ पकडने के मामले बढने से वाकई हालत गंभीर है।

दिल्ली पुलिस के खाकी रिश्वतखौर सीबीआई के अंटे चढे, 5 महीने में दर्जन अरेस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

इस गैंग ने कई पुलिसकर्मियों से वसूली की थी। वहीं अब ये हालात है कि सीबीआई के द्वारा रंगे हाथ पकडने के मामले बढने से वाकई हालत गंभीर है। जाहिर है कि थाना लेबल पर घूसखोरी टॉप पर है। दरअसल रिश्वती मामले में हर कोई आम शख्स सीबीआई तक नहीं पहुंच पाता है।कई मामलों में पीडित कानूनी पचडों से बचने या खुद गलत होने से शिकायत नहीं करता।

एस.डी.सेठी, नई दिल्ली। दिल्ली। देश की राजधानी पुलिस के दर्जन से ऊपर कारिंदे पिछले- 4-5 महीने में ही रिश्वत लेते हुए सीबीआई के हत्थे चढ चुके हैं। पुलिस के द्वारा रिश्वत वसूली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे दिल्ली पुलिस की छवि पर बट्टा लग रहा है। इसके अलावा पुलिस वालों से भी वसूली के मामले भी सामने आए हैं। बता दें कि फरवरी - 2022 में पुलिस वालों को ब्लैकमेल करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड हुआ था।जिनमें एक सब-इंस्पेक्टर और उसका बेटा भी शामिल था।

इस गैंग ने कई पुलिसकर्मियों से वसूली की थी। वहीं अब ये हालात है कि सीबीआई के द्वारा रंगे हाथ पकडने के मामले बढने से वाकई हालत गंभीर है। जाहिर है कि थाना लेबल पर घूसखोरी टॉप पर है। दरअसल रिश्वती मामले में हर कोई आम शख्स सीबीआई तक नहीं पहुंच पाता है।कई मामलों में पीडित कानूनी पचडों से बचने या खुद गलत होने से शिकायत नहीं करता। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट के वेलकम थाने में सीबीआई ने रेड की। एक हेड कांस्टेबल प्रदीप 13000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया। यह हवलदार अवैध परमिट बस चलाने के लिए पैसे वसूलता था। इसी कडी मे बीते महज 5 महीने में ही सीबीआई द्वारा 5000 रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक की रिश्वत वसूलते 10 से ज्यादा दिल्ली पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिश्वतखोरी के मामलों पर महकमें के रिटायर्ड पुलिस अफसर का कहना है कई मर्तबा पुलिसकर्मियों पर रिश्वत के आरोप लगते रहते हैं।कई मामलों में जांच अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए जाते है। लेकिन सीबीआई के द्वारा रंगे हाथ पकडने के बढ रहे मामले वाकई खासे गंभीर हैं। इससे महकमें की छवि और भरोसे पर भी प्रभाव पडता है। लेटस्ट 12 मार्च को वेलकम थाने के हवलदार प्रदीप तौमर को 13 हजार रूपये की रिश्वत लेते सीबीआई ने पकडा था। 25 फरवरी नंद नगरी थाने के हेडकांस्टेबल पंकज को 40 हजार रूपये रिश्वत लेते पकडा।वह अवैध निर्माण के बूते रिश्वत वसूल रहा था। 15 फरवरी को हौजखास थाने के सब-इंस्पेक्टर को 5 हजार रूपये रिश्वत लेते दबोचा गया। एएसआई स्कूटर वापस दिलाने के लिए पीडित से रिश्वत वसूल रहा था।8- फरवरी को जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसआई को चोरी के केस में कमजोर धारा लगाने के लिए 45 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।10 फरवरी को कोतवाली दरियागंज ट्रैफिक सर्किल के हेडकांस्टेबल अमन को कूडा-कचरा उठाने वाले गाडी मालिक से 5000 रूपये की रिश्वत लेते सीबीआई ने पकडा। 5 जनवरी को सागर पुर थाने में तैनात एएसआई हरबंश लाल को अरेस्ट नहीं करने की ऐवज में 1 लाख रूपये की रिश्वत डिमांड केस में 20 हजार रूपये लेते सीबीआई ने रंगे हाथों पकडा। वहीं 29 दिसंबर को सोनिया बिहार थाने में तैनात हेडकांस्टेबल रवींद्र सिंह राठी और कांस्टेबल जितेंद्र को अवैध कंस्ट्रक्शन करने के लिए 8000 रूपये लेते सीबीआई ने पकडा, 7 दिसंबर को आनंद विहार बस अड्डे के बाहर बस खडी करने के लिए 5000 रूपये मंथली लेने के आरोप में सीबीआई ने हेडकांस्टेबल अमरपाल और दलाल को दबोचा। 13 नवंबर को नई दिल्ली के बाराखंभा रोड में दर्ज एक केस से बचाने के लिए एएसआई राजेश यादव ने 4.5 लाख रूपये रिश्वत की डिमांड की। जिसमें राजेश यादव और वरूण चींचीं पकडे गए। ऐसे और भी कई मामले हैं जहां रिश्वत के बल पर अवैध को वैध कर दिया गया।

होली वाले दिन चंद्रग्रहण का क्या होगा त्योहार पर असर?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पिछली बार तिथियों के झोल में होली और होलिका दहन भी दो दिन हो गया था। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार होली वाले दिन ही लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में आप सभी के मन में तरह तरह की शंकाएं होंगी। होली पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा और होलिका दहन को लेकर चर्चाएं जरूर कर रहे होगें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 25 मार्च यानी होली के दिन लगने वाला चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। अतः भारत में इसका मान भी नहीं होगा और न ही होली के त्योहार पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में होली 24 एवं 25 मार्च को मनाई जाएगी। 24 को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को रंगोत्सव होगा। साल 2024 का पहला चंद्रग्रहण 25 मार्च को होली के दिन लगने जा रहा है। वैसे तो ग्रहण काल अशुभ माना जाता है लेकिन यह चंद्रग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक मान्य नहीं होने से इसका प्रभाव होली के त्योहार पर नहीं पड़ेगा। अन्य ज्योतिषाचार्य के कथन अनुसार 25 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपच्छाया चंद्र ग्रहण है। इस दौरान चंद्रमा केवल पृथ्वी की छाया के बाहरी किनारों से गुजरेगा। यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि पर लगेगा। इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार दिन में 10 बजकर 23 मिनट से दोपहर 03 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। 04 घंटे 36 मिनट की अवधि वाला यह चंद्रग्रहण यूरोप, उत्तर-पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में देखा जा सकेगा। यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा।

शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य ने सलाह दी है कि चंद्रग्रहण के कारण होली को लेकर किसी दुविधा में न पड़ें। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर होली मनाई जाती है। इस दृष्टि से इस साल 24 मार्च को होलिका दहन होगा। अगले दिन 25 मार्च को रंग खेला जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च रात 11:13 बजे से रात 12: 27 बजे तक रहेगा। होलिका दहन की अवधि कुल 01 घंटा 14 मिनट तक है।

ग्रेटर नोएडा में हुई मोटो जीपी बाइक रेसिंग में घपले का आरोप, जेवर विधायक ने की जांच की मांग

ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी बाइक रेसिंग में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। इसके लिए जेवर विधायक ने जांच की मांग की है। सरकारी पैसे को आयोजनकर्ता कंपनी द्वारा हड़पने की आशंका को देखते हुए ऑडिट होना जरूरी है। बाइक रेसिंग के लिए ट्रैक तैयार करने वाली कंपनी सॉलिटियर इंजीनियरिंग जेपी समूह हाउस कीपिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली कंपनी समेत अन्य कंपनियों का भुगतान बकाया है।

ग्रेटर नोएडा। मोटो जीपी 2023 के आयोजन में अनियमितता की जांच की मांग जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने की है। उन्होंने इस संबंध में मोटो जीपी बाइक रेसिंग के आयोजन के तीन माह बाद ही मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सरकार की ओर से आयोजनकर्ता कंपनी को दी गई धनराशि व अनुबंध का ऑडिट कराने की मांग की थी।

फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने रेस का किया था आयोजन

इन्वेस्ट यूपी ने इस जांच के लिए यमुना प्राधिकरण को अधिकृत किया था, लेकिन अभी तक यमुना प्राधिकरण ने जांच नहीं की है। विधायक ने यमुना प्राधिकरण से जांच रिपोर्ट मांगी है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर सितंबर 2023 में पहली बार मोटो जीपी बाइक रेसिंग का आयोजन किया गया था। भारत में फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने मोटो जीपी बाइक रेसिंग का आयोजन किया था।

इसके लिए प्रदेश सरकार ने फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ अनुबंध किया और आयोजन के लिए 18 करोड़ रुपये दिए थे। विधायक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स को दी गई धनराशि का ऑडिट और अनुबंध की शर्त के पालन की जांच कराने की मांग की है। विधायक ने कहा कि आयोजकों द्वारा बरती गई अनियमितता को देखते हुए जांच कराना जरूरी है।

कई कंपनियों का है बकाया

आयोजनकर्ता कंपनी ने स्पेन की डोरना कंपनी को लाइसेंस शुल्क का 120 करोड़ रुपये भुगतान नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह राशि दिलाने की बात कहकर गुमराह किया जा रहा है। बाइक रेसिंग के लिए ट्रैक तैयार करने वाली कंपनी सॉलिटियर इंजीनियरिंग का छह करोड़, जेपी समूह का 14 करोड़, हाउस कीपिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली कंपनी का पांच करोड़ समेत अन्य कंपनियों का भुगतान बकाया है।

गुरुग्राम में इन नस्ल के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध, नगर निगम नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन; देखें लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

प्रत्येक कुत्ते के मालिक को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम में करवाना जरूरी है। निगम में कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये हैं। एक वर्ष बाद 250 रुपये फीस देकर कुत्ते के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जा सकता है।केंद्र सरकार ने खूंखार कुत्तों की 23 प्रजातियों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है। गुरुग्राम नगर निगम प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा।

गुरुग्राम। अगर आप घर में कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो पहले कुत्तों की प्रतिबंधित प्रजातियों के बारे में जान लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने खूंखार कुत्तों की 23 प्रजातियों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है। ऐसे में अगर खूंखार प्रजाति का कुत्ता पाला तो गुरुग्राम नगर निगम में रजिस्ट्रेशन भी अटक सकता है।

हालांकि, फिलहाल यह आदेश निगम में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन निगम अधिकारियों का कहना है कि आदेशों का पालन किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष सिंगला ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में अब तक 1500 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। खूंखार प्रजाति के कुत्तों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

प्रत्येक कुत्ते के मालिक को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम में करवाना जरूरी है। सार्वजनिक स्थल पर कुत्ते को ले जाते समय मुंह पर नेट कैप पहनाने और कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाते समय शिट बैग लेकर जाने का नियम है। निगम में कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये हैं। एक वर्ष बाद 250 रुपये फीस देकर कुत्ते के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जा सकता है।

कोर्ट पहुंच गया था मामला

11 अगस्त 2022 को सिविल लाइंस क्षेत्र में एक घरेलू सहायिका को डोगो अर्जेंटीनो प्रजाति के एक कुत्ते ने काट लिया था। घरेलू सहायिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके अलावा सिविल लाइंस में ही रहने वाले एक एडवोकेट ने भी इस मामले में कोर्ट में केस दायर कर दिया। इसके बाद पीड़िता मुन्नी ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया। बाद में यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।

इन खूंखार प्रजातियों पर लगाया प्रतिबंध

पिटबुल टेरियर्स, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडाग, बोअरबोएल, कांगल, टार्नजैक, बैंडोग, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, राटविलर, रोडेशियन रिजबैक, कैनारियो, अकबाश और मास्को गार्ड डाग, वोल्फ डाग और जर्मन शेफर्ड को खूंखार प्रजातियों में शामिल किया गया है।

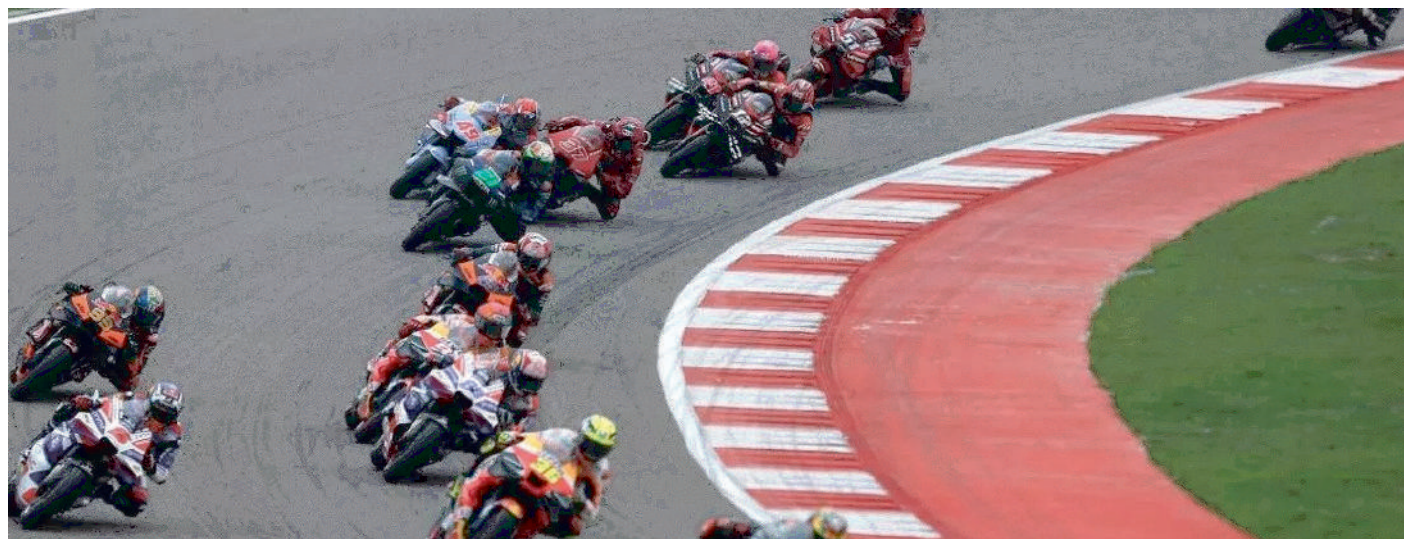

ग्रेटर नोएडा के 19 गांव स्मार्ट विलेज की लिस्ट में शामिल, मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं; यीडा ने खोला खजाना

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण ने स्मार्ट विलेज की लिस्ट में शामिल किए गए गावों के लिए खजाना खोल दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 19 गांवों को स्मार्ट बनाने पर प्राधिकरण 156 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्राधिकरण ने 13 मार्च को हुई बोर्ड बैठक में गांव विकास के लिए बजट आवंटित कर दिया है। प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में ग्राम विकास के लिए 129 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने अधिसूचित गांवों को स्मार्ट बनाने और उनके विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में यमुना प्राधिकरण 19 गांवों को स्मार्ट बनाने पर 156 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके साथ ही गांवों का संरचनात्मक ढांचा सुधारने पर 186.15 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

स्मार्ट विलेज की सूची नए गांव शामिल

प्राधिकरण ने स्मार्ट विलेज की सूची में नए गांव शामिल किए हैं। यमुना प्राधिकरण अभी तक 29 गांवों की जमीन को अपने मास्टर प्लान में प्रस्तावित सेक्टरों को विकसित करने के लिए अधिगृहीत या सहमति से क्रय किया है। पंचायती राज व्यवस्था समाप्त होने के बाद इन गांवों के विकास की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण पर है।

प्राधिकरण ने गांवों के मौजूदा ढांचे के साथ ही उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करा रहा है। इस सूची में अभी तक 19 गांव शामिल हो चुके हैं। प्राधिकरण ने 13 मार्च को हुई बोर्ड बैठक में गांव विकास के लिए बजट आवंटित कर दिया है।

प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में ग्राम विकास के लिए 129 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें से प्राधिकरण मात्र 56.63 करोड़ रुपये खर्च कर सका है। इस वर्ष ग्राम विकास के लिए 186.15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसी तरह गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 156 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वित्त वर्ष में गांवों को स्मार्ट बनाने पर प्राधिकरण ने 68 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इन गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना

प्राधिकरण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए गांवों को स्मार्ट विलेज सूची में शामिल किया है। इसमें आच्छेपुर, उस्मानपुर, फतेहपुर अट्टा, चकबीरमपुर, कादरपुर, रबूपुरा, महमदपुर गुर्जर, चांदपुर, जगनपुर शामिल हैं।

गांवों में यह विकास कार्य होंगे

स्मार्ट विलेज में डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सीवर, पानी की लाइन, ऑप्टिकल फाइबर लाइन, बारात या सामुदायिक केंद्र आदि शामिल हैं। गांवों में विकास कार्य एवं स्मार्ट विलेज के लिए आगामी वित्त वर्ष में बजट को बढ़ाया गया है। स्मार्ट विलेज के लिए कुछ नए गांवों को शामिल किया गया है। जल्द ही इन गांवों में विकास कार्य के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

- डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

CAA लागू होने के बाद पुलिस आज हाई अलर्ट पर, अतिरिक्त सुरक्षाबल किए गए तैनात

देश में CAA लागू होने के बाद आज शुक्रवार को पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। जिन इलाकों में नमाज अदा की गई है वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। डीसीपी सिटी ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि हम पुलिस बल के साथ भ्रमण कर रहे हैं। चुनाव इस वक्त बड़ा मुद्दा है। इसके बाद कई त्योहार आनेवाले हैं।

गाजियाबाद। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू होने के बाद आज शुक्रवार को पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। जिन इलाकों में नमाज अदा की गई है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। डीसीपी सिटी ज्ञानंजय सिंह पुलिस बल के साथ भ्रमण कर रहे हैं।

ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि त्योहार को लेकर हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। हमारा कोई विषय नहीं है। चुनाव इस वक्त बड़ा मुद्दा है। इसके बाद ई त्योहार आनेवाले हैं। सोशल मीडिया पर भी हमलोग नजर रखे हुए हैं। इस पर एक सेल अलग से काम कर रही है। फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं है। शहर में अमन चैन है।

बीजेपी टिकट हासिल करने के लिए क्या करना होता है? किस आधार पर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति नामों को मंजूरी देती है?

भाजपा आखिर किस आधार पर किसी को पार्टी का उम्मीदवार बनाती है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भाजपा चुनावों से ठीक पहले या चुनावों की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों की तलाश शुरू नहीं करती है बल्कि उसकी यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है।

नीरज कुमार दुबे

लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा अबकी बार 400 पार का नारा लगा रही है। यह नारा हकीकत बनता है या नहीं यह तो चुनाव परिणाम बाद ही पता चलेगा लेकिन इतना तो है कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से भाजपा इस समय अन्य दलों से काफी आगे नजर आ रही है। आम चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले भाजपा अपने उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर चुकी है। इस दौरान देखने को मिला कि सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि जनता भी भाजपा उम्मीदवारों की सूची में शामिल नामों को जानने के लिए उत्सुक थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि भाजपा की उम्मीदवारी हासिल करना ही जीत की गारंटी है। शायद इसी गारंटी के लालच में ही चुनावों से पहले कई नेताओं ने दल बदल कर भाजपा का दामन थाम लिया तो कई ऐसे नेता भाजपा में लौट आये जोकि कुछ समय पहले कहीं और चले गये थे।

चुनावों से पहले जिस तरह भाजपा से लोकसभा चुनाव का टिकट हासिल करने के लिए होड़ दिखी वह अभूतपूर्व थी। हमने भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में कई ऐसे लोगों को भी पाया जोकि भाजपा से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन वहां इसलिए आ गये थे ताकि पार्टी नेताओं को देश के लिए काम करने के अपने विजन के बारे में बता कर उम्मीदवारी हासिल कर सकें। इन लोगों का विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भाजपा का टिकट हासिल करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की परिक्रमा करनी जरूरी नहीं है और अब सिर्फ योग्यता के आधार पर ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। देखा जाये तो यह लोग कुछ हद तक सही भी थे लेकिन भाजपा के काम करने के तरीके से अनजान थे इसलिए जब वह सीधे लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे तो वहां खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे।

इसलिए आइये आपको समझाते हैं कि भाजपा आखिर किस आधार पर किसी को पार्टी का उम्मीदवार बनाती है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भाजपा चुनावों से ठीक पहले या चुनावों की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों की तलाश शुरू नहीं करती है बल्कि उसकी यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। मसलन जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसके लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन डेढ़ साल से चल रहा है। अभी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की जो दो बैठकें हुई हैं उनमें सिर्फ उन नामों पर मुहर लगाने का काम हुआ है जोकि पार्टी की विभिन्न समितियों ने केंद्रीय चुनाव समिति को तमाम तरह की रिपोर्टों के साथ संलग्न करके भेजे थे।

हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं उसके मुताबिक आइये आपको समझाते हैं जब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें क्या होता है। उदाहरण के लिए लोकसभा चुनावों की ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वाली बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों को सबसे पहले यह बताते हैं कि आज किन राज्यों की सीटों पर चर्चा होनी है। इसके बाद उस राज्य से भाजपा मुख्यालय में पहले से आकर बैठे हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता, राज्य के पार्टी प्रभारी और यदि किसी केंद्रीय मंत्री के पास उस राज्य का प्रभार है तो उनको भी बैठक में बुला लिया जाता है। मान लीजिये कि उस राज्य में 25 सीटें हैं। सबसे पहले उन सीटों पर चर्चा की जाती है जहां किसी को फिर से मौका देना है। प्रदेश अध्यक्ष एक-एक कर सीट का नाम बोलते हैं और बैठक कक्ष में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर उस सीट के दावेदारों का परिचय फोटो के साथ एक-एक करके आता रहता है। सभी दावेदारों के आगे विभिन्न सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के अलावा यह भी लिखा होता है कि उन्होंने पार्टी के कार्यों में कितनी रुचि दिखाई, विवादों में कितना घिरे रहे, संसदीय कार्यों में कितनी रुचि ली, संसद में कितनी उपस्थिति रही, सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के अभियान में क्या योगदान दिया, स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार रहा, संसदीय क्षेत्र में जो वादे किये थे उन्हें कितना पूरा किया। इसके अलावा उस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों से संबंधित ग्राफ के अलावा उस सीट पर विपक्ष की ओर से खड़ी की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। राज्य के नेता एक-एक करके हर दावेदार के नाम के गुण और दोष बताते हैं। उसके बाद भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उन एजेंसियों की सर्वेक्षण रिपोर्ट दिखाते हैं जो भाजपा ने उस क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों को लेकर करवायी होती है। वह यह भी बताते हैं आरएसएस और उसके आनुषांगिक संगठनों की ओर से उस क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए क्या फीडबैक मिला है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य उन नामों पर अपनी राय रखते हैं और जो नाम तय होते जाते हैं उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव अलग से नोट करते रहते हैं। जिन नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति का कोई सदस्य या खुद प्रधानमंत्री उस पर आपत्ति जता दें तो फिर पार्टी की प्रदेश इकाई को उस सीट के लिए और नाम सुझाने के लिए कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नामों पर चर्चा करने के लिए आई प्रदेश इकाई टीम को कह दिया जाता है कि किसी भी निवर्तमान सांसद या पहले लड़ चुके उम्मीदवार को इस बार मौका नहीं दिया जायेगा इसलिए सभी नाम नये होने चाहिए।

इसी तरह एक के बाद एक अलग राज्यों के नेताओं को बुला कर चर्चा की जाती है। मान लीजिये कि एक दिन में चार राज्यों पर चर्चा हुई तो उन चार राज्यों की जिन सीटों के लिए नाम तय हो गये हैं उसे जारी करने से पहले एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाया जाता है और फिर मीडिया को नाम जारी कर दिये जाते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पार्टी की राज्यों की चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेजने से पहले सभी दावेदारों की सूची बनाती है। इस सूची में वह नाम तो होते ही हैं जो दावेदारों ने खुद आवेदन करके दिये होते हैं साथ ही इसमें वह नाम भी होते हैं जो भाजपा की स्थानीय इकाई, संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से भेजे गये होते हैं। इसके अलावा राज्यों में भाजपा के संगठन महासचिव या पूर्णकालिक कार्यकर्ता हमेशा इस बात की खोज करते रहते हैं कि समाज जीवन के जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य कर रहा हो उसे कैसे पार्टी से जोड़ा जाये और समय आने पर उसे चुनाव लड़ने का अवसर भी दिया जाये, ऐसे में यदि वह कोई नाम सुझाते हैं तो उसे भी इस सूची में शामिल किया जाता है। इसलिए आपको भाजपा की सूची में कई बार विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे प्रोफेशनल्स का नाम भी देखने को मिल जाता है जिन्होंने कभी टिकट के लिए आवेदन ही नहीं किया था। किसी राज्य के उम्मीदवारों को तय करते हुए यह भी ध्यान दिया जाता है कि वहां की सूची में अनुभवी नेताओं, युवाओं, महिलाओं, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त भागीदारी मिले। भाजपा के टिकट के लिए एक और जरूरी बात यह है कि व्यक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। पार्टी की सामान्य सदस्यता तो सभी को मिल जाती है लेकिन सक्रिय सदस्यता हासिल करने के लिए कुछ अनिवार्यताएं हैं जिन्हें पूरा करना होता है। लेकिन अक्सर उन लोगों को इन अनिवार्यताओं से छूट मिल जाती है जो बड़े नेता होते हैं और दल बदल कर भाजपा में आते ही टिकट हासिल कर लेते हैं। ऐसे नेताओं को अक्सर आपने देखा होगा कि वह सामान्य सदस्यता वाली पर्ची मीडिया को दिखाते हुए खुद के भाजपा में शामिल होने की घोषणा करते हैं और अगले ही दिन या कुछ ही घंटों में उम्मीदवारी भी हासिल कर लेते हैं। बहरहाल, भाजपा का टिकट हासिल करने की जो प्रक्रिया लोकसभा चुनाव में है वही विधानसभा और अन्य चुनावों में भी होती है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों को मंजूरी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति देती है और नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों के उम्मीदवारों के नामों को उस प्रदेश की चुनाव समिति मंजूरी देती है। भाजपा की उम्मीदवारी हासिल करने में परिवारवाद, नेताओं की परिक्रमा और धन बल की योग्यता आजकल मायने नहीं रखती लेकिन उम्मीदवार का मेहनती और भाग्यशाली होना भी जरूरी है।

अब रोड़ एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को मिलेगा कैशलैस ट्रीटमेंट, सरकार ने की शुरूआत

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 162 के तहत केंद्र सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। सरकार की ओर से इस प्रोग्राम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से शुरू किया गया है। जिसके मुताबिक मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुए सड़क हादसों में घायलों को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अब Road Accident के घायलों को Cashless Treatment दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Morth) की ओर से एक पायलट प्रोगाम की शुरूआत भी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से इस प्रोग्राम को किस शहर से और कब शुरू किया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार की ओर से देशभर में Road Accident को कम करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम की शुरूआत की गई है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं देने होंगे। बल्कि उनका इलाज कैशलैस (Cashless treatment) तरह से होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम को देश के किस शहर से शुरू किया गया है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

शुरू हुआ पायलट प्रोग्राम

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 162 के तहत केंद्र सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। सरकार की ओर से इस प्रोग्राम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से शुरू किया गया है। जिसके मुताबिक मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुए सड़क हादसों में घायलों को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

क्यों शुरू किया प्रोग्राम

सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सड़क हादसा होने के बाद गोल्डन आवर के दौरान घायलों को इलाज की जरूरत होती है। अगर समय पर इलाज मिल जाए तो इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि ऐसा ईकोसिस्टम बनाया जाए जिससे यह संभव हो पाए। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जमीनी स्तर पर अस्पताल और पुलिस के साथ समन्वय बनाएगा।

इस तरह मिलेगा फायदा

पायलट प्रोग्राम के मुताबिक सड़क हादसे में घायल होने वाले व्यक्ति को हादसे के बाद सात दिनों के अंदर कैशलैस इलाज मिल पाएगा। इसके साथ ही यह किसी भी तरह की श्रेणी की सड़क और वाहन के कारण हादसा होने पर दिया जाएगा। उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी। पीड़ित अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के हकदार होंगे।

अहम है प्रोग्राम

सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि चंडीगढ़ में शुरू किए गए इस पायलट प्रोग्राम के नतीजों की समीक्षा करने के बाद ही इस सुविधा को देश के अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा।

Skoda Epiq की पहली झलक आई सामने, अगले साल एंट्री मारेगी कंपनी की सबसे अफोर्डेबल EV

Skoda Epiq अपना बेस VW ID.2 के साथ साझा करती है। इस इलेक्ट्रिक कार का एक्सटीरियर डिजाइन मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज को अपनाता है। इसके बारे में कंपनी का कहना है कि इसमें स्मार्ट कार्यक्षमता और व्यावहारिकता एक साथ शामिल है। सामने की तरफ नया टेक-डेक फेस है। स्कोडा एपिक कॉन्सेप्ट का केबिन डुअल-टोन थीम के साथ आता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Skoda Auto ने अपनी सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा दिया है। नई Skoda Epiq इलेक्ट्रिक एसयूवी 2025 में लॉन्च की जा सकती है। कंपनी ने इसका नाम 'एपिक' शब्द से लिया है और ये लगभग 4.1 मीटर लंबी है, जो इसे स्कोडा कुशाक से थोड़ा छोटा बनाती है। आइए, कंपनी की नई EV के बारे में जान लेते हैं।

Skoda Epiq का डिजाइन

स्कोडा एपिक अपना बेस VW ID.2 के साथ साझा करती है। इस इलेक्ट्रिक कार का एक्सटीरियर डिजाइन मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज को अपनाता है। इसके बारे में कंपनी का कहना है कि इसमें स्मार्ट कार्यक्षमता और व्यावहारिकता एक साथ शामिल है। सामने की तरफ नया टेक-डेक फेस है। ग्रिल के किनारे नए टी-आकार के एलईडी डीआरएल हैं और नीचे मैट्रिक्स एलईडी तकनीक वाली हेडलाइट्स हैं। बम्पर में बड़े पैमाने पर वर्टिकल स्लैट हैं, जो हमें जीप एसयूवी की तरह नजर आते हैं। इसमें पीछे की ओर फ्लेयर्ड व्हील आर्च और टी-आकार की एलईडी टेललाइट्स जोड़े गए हैं।

Skoda Epiq का इंटीरियर

स्कोडा एपिक कॉन्सेप्ट का केबिन डुअल-टोन थीम के साथ आता है। मॉडल में टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 5.3-इंच वर्चुअल कॉकपिट और 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। स्कोडा का कहना है कि पूरे केबिन में वायरलेस चार्जिंग और 490 लीटर तक की बूट क्षमता सहित कई उपयोगी फीचर्स हैं।

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने फरवरी 2024 में जमकर बेची गाड़ियां, इधर भारतीयों ने उससे दोगुनी Wagon R खरीद डाली

चार्जिंग और रेंज

Skoda Epiq इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 400 किमी तक की रेंज प्रदान कर सकती है। इसकी कीमतें यूरोपीय बाजार में लगभग 25,000 यूरो (लगभग ₹23 लाख) के आसपास होंगी।

किरन खैर ने खरीदी Mercedes GLS, फिल्मों सितारों के बीच खूब फेमस है ये कार; जानिए कीमत और खासियत

Kirron Kher ने GLS 450 4Matic को चुना है जिसके पेट्रोल यूनिट की कीमत 1.21 करोड़ है जबकि डीजल इंजन वर्जन 1.37 करोड़ रुपये में उपलब्ध है। आपको बता दें कि दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं। GLS 600 का एक 4Matic Plus वेरिएंट भी है और इसकी कीमत ₹2.96 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम है। आइए इस लग्जरी कार के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ने हाल ही में Mercedes-Benz GLS luxury SUV खरीदी है। नई कार खरीदते हुए उनकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसे मर्सडीज के डीलर द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया था। मर्सडीज जीएलएस बॉलीवुड सितारों के बीच काफी पॉपुलर रही है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Mercedes-Benz GLS में क्या खास?

Kirron Kher ने GLS 450 4Matic को चुना है, जिसके पेट्रोल यूनिट की कीमत 1.21 करोड़ है, जबकि डीजल इंजन वर्जन 1.37 करोड़ रुपये में उपलब्ध है। आपको बता दें कि दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं। GLS 600 का एक 4Matic Plus वेरिएंट भी है और इसकी कीमत ₹2.96 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम है।

इंजन और स्पेसिफिकेशन

दोनों इंजन 3.0-लीटर 6-सिलेंडर यूनिट हैं। पेट्रोल इंजन 375 बीएचपी की अधिकतम पावर और 500 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है, जबकि डीजल इंजन 361 बीएचपी और 750 एनएम का आउटपुट देता है। दोनों इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़े हैं और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है। हाल ही में, मर्सिडीज-बेंज ने 2024 ई53 हाइब्रिड 4मैटिक+ को पेश किया था। यह सिस्टम एक शक्तिशाली 3.0-लीटर छह-सिलेंडर इंजन को जोड़ता है, जो 436 बीएचपी का उत्पादन करता है और 158 बीएचपी उत्पन्न करने वाली एकल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एएमजी स्पीडशिफ्ट टीसीटी 9जी ट्रांसमिशन में इंटीग्रेटेड है।

2024 KTM RC 8C की ग्लोबल मार्केट में एंट्री, केवल 100 लकी कस्टमर ही खरीद सकेंगे ये बाइक

केटीएम ने ग्लोबल मार्केट में 2024 KTM RC 8C को पेश कर दिया है। KTM RC 8C केवल यूरोप अमेरिका मैक्सिको कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। प्री-बुकिंग अमाउंट 1000 यूरो है और ग्राहक अपनी पसंदीदा डीलरशिप का चयन करके इसे बुक कर सकते हैं। इसे केवल 100 ग्राहक ही खरीद सकेंगे। आइए डिटेल्स जान लेते हैं।

नई दिल्ली। केटीएम ने ग्लोबल मार्केट में 2024 KTM RC 8C को पेश कर दिया है। आपको बता दें कि केवल 100 ग्राहक ही इसे खरीद सकेंगे। RC 8C एक ट्रैक-ओनली मोटरसाइकिल है और इसके लिए प्री-बुकिंग 20 मार्च को पर शुरू होगी। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

केवल इन लोगों को मिल सकेगी बाइक

KTM RC 8C केवल यूरोप, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। प्री-बुकिंग अमाउंट 1,000 यूरो है और ग्राहक अपनी पसंदीदा डीलरशिप का चयन करके इसे बुक कर सकते हैं।

इंजन और परफॉरमेंस

मोटरसाइकिल 889 सीसी एलसी8सी इंजन द्वारा संचालित है, जो अधिकतम 133 बीएचपी की शक्ति उत्पन्न करती है और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। ट्रैक-ओनली बाइक होने के नाते RC 8C में एक स्पेशल चेसिस है और इसमें रेसिंग कंपोनेंट का उपयोग किया गया है।

डिजाइन और डायमेंशन

वजन कम रखने के लिए KTM RC 8C को KTM RC16 से प्रेरित कार्बन केवलर बॉडीवर्क के साथ पेश किया गया है। इंजन और बॉडीवर्क को 25CrMo4 स्टील ट्यूबलर फ्रेम पर डेवलप किया गया है। केटीएम का कहना है कि सस्पेंशन को ट्रैक के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। 2024 केटीएम आरसी 8सी को धीमा करने के लिए ब्रेम्बो 19आरसीएस कोर्सा कॉर्टा रेडियल मास्टर ब्रेक सिलेंडर हैं, साथ ही ब्रेम्बो स्टाइलमा फ्रंट ब्रेक कैलीपर्स हैं, जो फ्रंट में 290 मिमी पूरी तरह से फ्लोटिंग ब्रेक डिस्क को पकड़ते हैं, जबकि पीछे की तरफ 230 मिमी के साथ ब्रेम्बो दो-पिस्टन कैलिपर है।

हिमाचल में हलचल, हरियाणा में परिवर्तन

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिलहाल 'स्टेटस को' दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर व्यक्त किया जा रहा है।

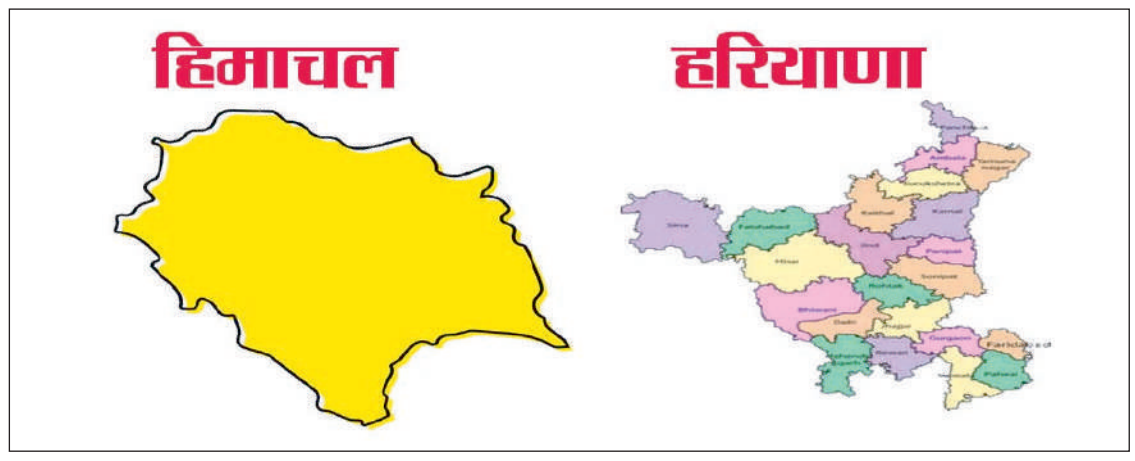

यदि कांग्रेस इन छह पूर्व विधायकों को फिर से स्वीकार लेती है, तो क्या होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब कांग्रेस इनको पार्टी में तो वापस ले सकती है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब इनको दोबारा विधानसभा का सदस्य नहीं बना सकेंगे। अब लोकसभा के चुनाव परिणामों का इंतजार है'

भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिलहाल 'स्टेटस को' दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर व्यक्त किया जा रहा है। चार दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मनोहर लाल की जमकर तारीफ की और दूसरे ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के तुरन्त बाद विधायक दल की बैठक हुई और उसमें मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी, जो फिलहाल हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, का नाम भाजपा विधायक दल के नए नेता के तौर पर पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और उसके साथ ही राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। अगले दिन उन्होंने विधानसभा में 48 विधायकों के समर्थन से अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। यह सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटित हुआ कि मीडिया इसकी भनक तक नहीं पा सका। लेकिन इस आप्रेशन में, जननायक पार्टी, जो ओमप्रकाश चौटाला के परिवार में राजनीतिक कुश्ती के चलते अस्तित्व में आई थी, हलाल हो गई।

जननायक पार्टी के दुष्यन्त चौटाला मनोहर लाल की सरकार में अपने दस विधायकों के बल पर उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे। नब्बे सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक हैं।

नायब सिंह सैनी की सरकार को सात निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया तो जननायक दुष्यन्त की जरूरत नहीं रही। सब जानते हैं कि राजनीति में बिना जरूरत कोई किसी को नहीं ढोता। कहा जा रहा है कि दुष्यन्त हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों में से दो सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा एक सीट देने को तैयार थी। पिछले पांच साल में जननायक पार्टी ने अपना जनाधार दुष्यन्त चौटाला की कार्यप्रणाली के चलते खोया है और ओमप्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो यानी इंडियन नैशनल लोकदल, अपनी तमाम कलाबाजियों के बावजूद हरियाणा में पुनः जडें. नहीं जमा सकी। भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला परिवार के इस राजनीतिक पतन को देख लिया था, लेकिन चौटाला परिवार शायद जानकर भी अनजान बना हुआ था। इतना ही नहीं, दुष्यन्त चौटाला तो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था। यहां तक कि दुष्यन्त अपने ही घर में टूट रही दीवारों की आवाज नहीं सुन सका। उसके दस विधायकों में से पांच उसका साथ छोड़ गए। कुल मिलाकर चार विधायक उसके पास बचे। भाजपा पिछले कुछ समय से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से देश में सामाजिक समरसता का ऐतिहासिक प्रयोग कर रही है। उसी प्रयोग के चलते नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वे ओबीसी श्रेणी से आते हैं जिससे पूरे राज्य में एक गहरा संदेश गया है। सोनिया कांग्रेस के राहुल गान्धी जब पूरे देश में घूम घूम कर यह घोषणा कर रहे हैं कि यदि वे प्रधानमंत्री बन गए तो वे भारतीय सामाजिक संरचना को राजनीति की बिसात पर 'जाति जनगणना' के नाम पर तार-तार करके रख देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने बिना शोर-शराबा किए नायब सिंह को मुख्यमंत्री बना कर व्यावहारिक धरातल पर हरियाणा में एक नया प्रयोग किया है। इससे हुड्डा परिवार व चौटाला परिवार दोनों सकते में हैं। न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। ऐसे समय जब सोनिया गान्धी, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, लालू यादव, अखिलेश यादव व एमके स्टालिन अपने परिवार से बाहर न देखने को तैयार हैं और न ही निकलने को तैयार हैं, नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना देश में परिवारवाद की राजनीति पर गहरा आघात है।

राजनीति के धुरंधर पंडित भी भाजपा की इस सांगठनिक कुशलता पर सिर धुनते नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्रियों के चयन के समय सबको चौंकाया था। राजनीतिक विश्लेषणों की शब्दावली में चाहे इसे चौंकाना कहा जाए, लेकिन यह भारतीय राजनीति में ऐसा प्रयोग कहा जा सकता है जो कई स्थापित मिथकों को तोड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने जहां भारतीय जनतंत्र में परिवारवाद का वृक्ष रोपने की कोशिश की, जिसकी देखादेखी दूसरे राजनीतिक दलों में भी यह प्रदूषण फैला, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसी 'जन' को राजनीति के केन्द्र में स्थापित करने की कोशिश की जिसके बलबूते 'जनतन्त्र' चलता है। हरियाणा में मनोहर लाल से नायब सैनी तक के इस प्रयोग के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में हुए धमाके की पुनः विवेचना करना भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बहुमत होते हुए भी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की पराजय और भाजपा के हर्ष महाजन की विजय के बाद के घटनाक्रम को देखना भी जरूरी है। फिलहाल प्रदेश विधानसभा में 62 सदस्य हैं। छह सदस्यों की सदस्यता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने इस कारण से समाप्त कर दी है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के स्थान पर भाजपा के प्रत्याशी को वोट दे दिया था। इस समय सरकार चलाने के लिए बत्तीस सदस्यों की जरूरत है। भाजपा के पास पच्चीस सदस्य हैं। तीन निर्दलीय उसके साथ हैं जिन्होंने हर्ष महाजन को वोट दिया था। इसका अर्थ हुआ कि हिमाचल में सरकार बनाने के लिए भाजपा को चार और सदस्य दरकार हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह की गतिविधियों को देखते हुए प्रश्न पैदा होता है कि क्या भाजपा इस समय हिमाचल में सरकार बनाने से गुरेज कर रही है और उसने सुखविन्दर सिंह सुक्खू की सरकार को फिलहाल 'स्टेटस को' दिया हुआ है? यदि सचमुच ऐसा है तो भाजपा ने कांग्रेस सरकार को यह 'स्टेटस को' क्यों दिया हुआ है? दूसरे प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि भाजपा पर आम तौर पर पारिवारिक राजनीतिक दल आरोप लगाते रहते हैं कि वह उनकी सरकार जोड़-तोड़ से गिरा रही है जो लोकतन्त्र की मूल भावना के खिलाफ है।

इसके लिए पूर्व में कर्नाटक व मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है। शायद हिमाचल प्रदेश में भाजपा आसन्न लोकसभा चुनावों को देखते हुए इससे बचना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनावों में, जो अगले महीने होने वाले हैं, यदि भाजपा प्रदेश की चारों सीटों पर जीत जाती है, जिसका चुनावों के परिणाम का पूर्वानुमान लगाने वाले पंडित संकेत कर रहे हैं, तो भाजपा क्या तब भी प्रदेश कांग्रेस सरकार को दिया हुआ यह 'स्टेटस को' जारी रखेगी, यह लाख टके का सवाल आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पूछा जा रहा है।

राजनीति की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर न में ही देगा। इसमें एक पेंच अब और भी फंस गया है। यदि रिक्त हुए छह स्थानों के लिए चुनाव हो जाते हैं और ये सीटें लोकसभा के चुनावों के साथ ही भाजपा के खाते में आ जाती हैं, तब तो भाजपा पर जोड़-तोड़ से सरकार बनाने का आरोप भी नहीं लग सकता। लेकिन एक दूसरी सम्भावना को भी देखना होगा। यदि कांग्रेस इन छह पूर्व विधायकों को फिर से स्वीकार लेती है, तो क्या होगा। राजनीति सम्भावनाओं का खेल है। अब कांग्रेस इनको पार्टी में तो वापस ले सकती है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब इनको दोबारा विधानसभा का सदस्य नहीं बना सकेंगे। उनके पास पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार तो है, लेकिन एक बार सदस्यता समाप्त हो जाने पर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सामाजिक समरसता का प्रयोग किया है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार को 'स्टेटस को' पर रखा हुआ है। अब सभी पक्षों को लोकसभा के चुनावों के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

संपादक की कलम से

पाकिस्तान बसाने को सीएए नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की व्याख्या ही बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, जो भावोत्तेजक हैं। उनकी मंशा हिंदू-मुसलमान से आगे बढक़र आर्थिक संसाधनों और स्थितियों पर केंद्रित करने की है, ताकि राजनीति की दिशा और दशा बदली जा सके। हालांकि ऐसी संभावनाएं नगण्य हैं। संयुक्त राष्ट्र नागरिकता को व्यक्तिपरक सुरक्षा का बुनियादी तत्त्व मानता है और प्रताड़ित, शोषित, मानवाधिकार कुचलन के शिकार लोगों को 'शरणार्थी' के तौर पर किसी भी देश में प्रवेश करने को 'मानवीय कर्म' मानता है। संयुक्त राष्ट्र ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते का भी जिक्र करता है, जिसके तहत शरणार्थियों को नागरिकता भी दी जा सकती है। केजरीवाल ने उत्तेजित अवस्था में कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत में बसाने का कानून बनाया गया है। कल हमारे देश में चोरियां, डकैतियां, बलात्कार होंगे। जगह-जगह दंगे भी भडक़ेंगे। देश की सुरक्षा-व्यवस्था का क्या होगा? केजरीवाल का आकलन है कि अब जो पलायन होगा, वह भारत-विभाजन से भी बड़ा और खतरनाक होगा। केजरीवाल के मुताबिक, तीनों पड़ोसी देशों से 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का पलायन हो सकता है। भारत सरकार उन्हें कहां रखेगी? कहां घर देगी? कहां खाने को अनाज देगी? कितनी नौकरियां और रोजगार दिए जा सकेंगे? देश के आर्थिक संसाधन तो सीमित हैं। हमारे नौजवानों के लिए नौकरी, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं और भाजपा ने देश के भीतर एक और पाकिस्तान को बसाने का कानून बनाया है। केजरीवाल ने सीएए को भाजपा का वोट बैंक तैयार करने की रणनीति करार दिया है।

बहरहाल केजरीवाल के अपने तर्क और राजनीति-शास्त्र हो सकते हैं। वह सीएए पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लिहाजा आर्थिक संसाधनों के आधार पर भावोत्तेजक राजनीति कर रहे हैं। विभाजन के दौर का वीभत्स और त्रासद सरकारी आंकड़ा यह है कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश), अफगानिस्तान तीनों पड़ोसी देशों से 72 लाख के करीब लोगों ने पलायन किया था। हालांकि अनौपचारिक आंकड़े ये हैं कि तब 2 या 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने पलायन किया होगा! ये आंकड़े विभिन्न संगठनों और मीडिया प्रतिनिधियों ने जुटाए थे। भारत-विभाजन से ज्यादा खौफनाक घटनाक्रम उस दौर में कोई और नहीं हुआ। हालांकि कुछ सालों के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा और हजारों नागरिकों ने, चीन से पलायन करके, भारत में शरण मांगी थी। तब के गरीब भारत ने उन्हें भी सम्मान से 'शरणार्थी' बनाया। आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल के धर्मशाला में काम कर रही है। आज भी भारत के कई शहरों में तिब्बती ऐसे बसे हैं मानो वे भारत के ही नागरिक हों! दरअसल सीएए कोई निरंतर प्रक्रिया नहीं है। जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 तक आवेदन किया है अथवा भारत में शरणार्थी बने हैं, उन्हीं पर सीएए के तहत फिलहाल विचार किया जाएगा। यह तारीख सरकार ने तय की है, लेकिन वह यह भी मानती है कि इन तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीडऩ, अपहरण, धर्मांतरण, जबरन निकाह, पूजा-स्थलों के विध्वंस और अन्य अत्याचार लगातार जारी रहे हैं। फिर यह तारीख किस आधार पर तय की गई है? 1947 के बाद वाले दौर में भारत अपेक्षाकृत बहुत गरीब था, लेकिन आज तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। सीएए पर जनता को उकसाना, भडक़ाना नहीं चाहिए।

राय

केवल और केवल अनुराग

सियासत के अद्भुत प्रतीक और शिनाख्त के पद्चिन्हों में राजनीतिक सपूत चुनने की कवायद में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि सामने आ रही है। पांचवीं बार हमीरपुर लोकसभा के अपने अभेद्य दुर्ग पर अनुराग ठाकुर को भाजपा, लोकसभा में मुकाम दिखा रही है। शिमला से सुरेश कश्यप पर भरोसा जताने के बावजूद मंडी का जौहर दिखाने में भाजपा की सियासी किफायत और कांगड़ा की दौड़ में हिम्मत दिखाने की कंजूसी अभी सूची से बाहर नहीं आई, लेकिन पार्टी का जलबा इस बार हमीरपुर संसदीय सीट के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रभुत्व की मांद में जरूर नई कहानी लिखना चाहेगा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एकतरफा जीत के दो शंखनाद हुए थे, तो मंडी में भाजपा का वर्चस्व लोकसभा चुनाव की तासीर में पूर्व सरकार की छवि की पहरेदारी में क्या नया हासिल करता है, यह देखना होगा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम की छत्रछाया में कोई नया नाम, कोई नया दांव, अपनी परख के हथौड़े की तरह टन-टन कर रहा है, तो कांगड़ा में भाजपा की सूची उस शोहरत से मुकाबिल है जहां वर्तमान सांसद किशन कपूर ने सात लाख से अधिक वोट जुटा कर ऐतिहासिक काम किया था। लोकसभा चुनाव की पात्रता में विधानसभा चुनाव की दक्षता का ईनाम क्या होगा, इसका फैसला कांग्रेस को भी कांगड़ा में करना है। सुक्खू सरकार के गठन और सत्ता के संगठन में दस विधायकों की जुंबिश लगा कांगड़ा के जिस आधार ने भाजपा को निराधार किया था, उसके आश्रालय में संसदीय चुनाव की अनुगूंज चंबा तक आंखें खोल कर देख रही है। जिला से कुल दो मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, चंद कैबिनेट रैंक और कुछ नियुक्तियों की पैमाइश के बूते कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का शीर्षासन इसलिए भी देखा जाएगा, क्योंकि सुधीर शर्मा जैसे चेहरे को दरकिनार करके पार्टी अपने वजूद की नई पैरवी कर रही है। यहां से सत्ता के पाले में जितने पद भरे हैं, उनमें से शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया का रुतबा अब हाथों में व्हिप लेकर अपनी मंजिलें बता रहा है। तमाम नियुक्तियों और तरह-तरह के पदभारों से सुसज्जित चेहरों के बीच केवल केवल सिंह पठानिया क्यों लोकसभा चुनाव से पूर्व अलग नजर आने लगे हैं, यह बदली कांगड़ा की सियासत में सरकार के खास नजर आने लगे हैं। केवल सिंह का गैर परिवारवाद तथा कभी कांगड़ा की ललकार रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया के व्यूह चक्र से निकल कर मुख्य सचेतक तक पहुंचना, वीरभद्र सिंह की आभा में चलती रही पार्टी की नई प्रतिभा है। कांग्रेस बदल रही है और बदल रहा है इसकी आभा का केंद्र। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस महज सत्ता नहीं सत्ता का नया पौधारोपण भी है। इस लिहाज से यह सरकार, सरकार के मुखिया तथा उपमुख्यमंत्री की सबसे बड़ी परीक्षा का द्वार भी है। सरकार इसी संसदीय सीट से पार्टी व दो सहयोगी निर्दलीयों समेत पांच विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा कर अपना रास्ता साफ करती हुई दिखाई दी है, लेकिन अपने कांटों के बाहर भाजपा के साम्राज्य की दीवारों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हस्ताक्षर स्पष्ट हैं। हिमाचल के अभिप्राय में मोदी सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा अगर सामने आता रहा, तो प्रदेश का एकमात्र सांसद अनुराग ठाकुर ही क्रियाशील रहा। केंद्रीय संस्थानों की पैरवी में एम्स, आईआईएचएम, हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज, बल्क ड्रग पार्क, केंद्रीय विश्वविद्यालय का देहरा परिसर, पीजीआई का सेटेलाइट सेंटर, ट्रिपल आईआईटी व खेलो इंडिया का उत्कृष्ट केंद्र खोलने के कर्णधार रहे अनुराग ठाकुर हिमाचल में रेल विस्तार के हर आयाम पर एकमात्र आशा बनकर उभरे हैं। हिमाचल के खाते में चलती नई ट्रेनें अगर ऊना को डेस्टिनेशन बना रही हैं, तो इन हरी झंडियों का जवाब फिलहाल आसान नहीं है।

भूपिंदर सिंह

विद्यार्थियों के लिए फिटनेस कार्यक्रम

कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडऩे व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। विद्यार्थी को कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो उसे फिटनेस कार्यक्रम देना होगा'

वर्षों से स्कूली स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात इस कॉलम के माध्यम से हो रही है, मगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी या निजी स्कूल अपने यहां फिटनेस कार्यक्रम लागू करने में नाकाम रहा है। कई बार नए शिक्षा सत्र शुरू होकर खत्म हो गए, मगर फिटनेस कार्यक्रम कहीं भी शुरू नहीं हो पाया है। मगर इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की सामान्य फिटनेस के लिए पहले की तरह अनिवार्य रूप से ड्रिल के पीरियड का प्रावधान किया है। शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, सट्रेंथ, इडोरैंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कॉलम के माध्यम से कई बार इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है।

किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है, जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिएं। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते-आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में व्यस्त रखने के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडऩा बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडिय़ों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए। हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना है। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करते थे। छात्र विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है।

पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडऩा तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडऩे व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ-साथ उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा। तभी हम सही अर्थों में अपनी अगली पीढ़ी को संपूर्ण शिक्षित कर सकते हैं।

हास्य रस

जेल जाने के फायदे

जेल जाने के फायदे इतने हैं कि आजकल जेल जाने की होड़ सी मची हुई है। एक सोचता है कि वह जेल चला गया तो मैं क्यों पीछे रहूं? इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और भ्रष्टाचार से होने वाले लाभों से तो आज हम सब परिचित हैं। तिहाड़ जेल तो मानो मंदिर बन गई है, जहां बड़े-बड़े वीवीआईपी डेरा डाले हुए हैं। कई बार तो मुझे वहम होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तिहाड़ जेल में ही तो नहीं हुआ था? जेल जाने से व्यक्तित्व का विकास होता है और वह नए कृतित्वों की तरफ अग्रसर होता है। जेल जाना तीर्थयात्रा के समान है। अब आदमी जेल से लौटता है तो उसका सार्वजनिक अभिनंदन होता है। चुनाव में टिकिट मिलता है और चुनाव जीतकर व्यक्ति सांसद या विधायक का पद सुशोभित करता है। फिर इन्हीं में से देश को मंत्री और मुख्यमंत्री मिलते हैं। कई महारथी तो ऐसे हैं, जो हमारे यहां जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। इन कर्णधारों व भाग्यविधाताओं से ही देश चल रहा है। जेल में जाने से बाल भी बांका नहीं होता, बल्कि जीवन का बाल-बाल संवर जाता है। घर में रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या नहीं रहती। यह सारी व्यवस्था सरकार जेलयात्री को स्वयं प्रदान करती है। चोरी, डकैती, गबन, घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से आर्थिक लाभ होता है और अर्थलाभ आज की दुनिया में सर्वोपरि है। आजकल भ्रष्टाचारी भी कम नहीं हैं, वे लाखों में नहीं, हजारों करोड़ों में हाथ साफ करते हैं। लोग हालांकि इसे काला कारनामा बताते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि भ्रष्टाचारी सदैव सफेदपोश रहता है।

मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकी रहती है और वह दनादन नोट छापता है और यह बात फायदे की श्रेणी में है। एक बार जेल जाने का सुख मुझे भी मिलने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा हुई और मैं बच गया। डिपार्टमेंटल इनक्वायरी से ही बात टल गई। सच कहूं तो मैं भी छोटा-मोटा भ्रष्टाचारी हूं ही। मौका पाते ही जितना कुछ संभव होता है, उस पर हाथ साफ कर देता हूं। जेल जा आता तो उससे दिल और खुल जाता और मैं आगे नए पायदानों पर कदम बढ़ाता। पिताजी थोड़े पुराने खयालों के हैं, वे अक्सर कहते रहते हैं कि सब कुछ करो, लेकिन सावधानी से करो। जेल जाना ठीक नहीं है। अब मेरे पिताजी को कौन समझाए कि जेल जाना माल मारने के लिए कितना असेंशियल हो गया है। पिताजी जब पटवारी थे, तब चार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे और पूरे पांच साल निलंबित रहे थे। इसलिए वे भ्रष्टाचार में सावधानी पर जोर देते हैं। आज की तारीख में जेलों में जाकर देखो तो हजारों सफेदपोश कैद हैं और वहां भी सारी सुख-सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। जेल प्रशासन भी हाड-मांस का बना है, उसे भी भूख लगती है और वे अपनी भूख इन्हीं भ्रष्टाचारियों के आसरे शांत करते हैं। इसलिए जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। जेल जाने के फायदे एक नहीं, अनेक हैं। मैं इसी जुगाड़ में इन दिनों लगा हूं कि किसी न किसी तरीके से कम से कम एक बार जेल यात्रा कर आऊं। भगवान की कृपा रही तो मैं जल्द ही इस काम में सफल हो जाऊंगा। फिर अपनी पौबारह होगी।

पूरन सरमा

इनसाइड

सोने के साथ चांदी भी हो रही है महंगी, अब 10 ग्राम गोल्ड के लिए इतने रुपये चुकाने होंगे

आज भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में इजफा हुआ है। कई शहरों में सोने-चांदी के रेट अलग हैं तो आपको सोना खरीदने से पहले एक बार इनके लेटेस्ट रेट को जरूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर कितने रुपये में मिल रहा है।

नईदिल्ली। 15 मार्च 2024 (शुक्रवार) को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की नई कीमत जारी हो गई है। आज भी इन दोनों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। इस हफ्ते लगातार सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में 10 ग्राम सोना के दाम 66,260 रुपये है। देश के सभी शहरों में गोल्ड की कीमत अलग होती है। चलिए, जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना कितने रुपये में ग्राम है।

चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

गुड रिटर्न के मुताबिक, आपके शहर में सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट्स-

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,260 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,110 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,110 रुपये है।

चेन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,820 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,110 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,260 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 66,260 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 66,160 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,260 रुपये है।

नागपुर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,160 रुपये है।

पुणे में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 66,110 रुपये है।

वायदा कारोबार में सोना-चांदी

वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने की कीमत 135 रुपये बढ़कर 65,730 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 135 रुपये या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 65,730 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 15,000 लॉट का कारोबार हुआ। वायदा कारोबार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 331 रुपये बढ़कर 75,557 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, मई डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 331 रुपये या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 25,338 लॉट में 75,557 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

पेटीएम पर 15 मार्च के बाद होंगे ये बदलाव, यूजर और मर्चेंट पर पड़ेगा असर

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की पार्टनर बैंकों में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में वापस (स्वीप-इन) किया जा सकता है...

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई ने Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध की समयसीमा 15 मार्च 2024 है। यानी कि कल से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सर्विस बंद हो जाएगी। इसका असरा यूजर या मर्चेंट पर पड़ेगा। अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए 15 मार्च के बाद से क्या बदलाव होने वाले हैं।

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर प्रतिबंध लगाने की भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। आरबीआई के इस फैसले का असर लाखों पेटीएम यूजर और मर्चेंट पर पड़ेगा। यह बदलाव कल से लागू हो जाएंगे।

क्या है प्रमुख बदलाव

जिनके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट है, वे 15 मार्च 2024 के बाद अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक के अनुसार, ब्याज, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा को जमा करने की अनुमति नहीं है।

हालाँकि, कोई भी आपके अकाउंट में उपलब्ध शेष राशि तक अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने रिफंड, कैशबैक की अनुमति दी है।

आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की पार्टनर बैंकों में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में वापस (स्वीप-इन) किया जा सकता है, जो पेमेंट्स बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा (प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 2 लाख रुपये) के अधीन है।

हालांकि, 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से साझेदार बैंकों में कोई नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अगर किसी का वेतन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में जमा किया जाता है, तो वे समय सीमा के बाद आपके खाते में ऐसा कोई क्रेडिट नहीं कर पाएंगे।

15 मार्च 2024 के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, इस असुविधा से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि यूजर 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक को यूपीआई से लिंक कर दें।

आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग करने वाले मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ये सुविधा 15 मार्च के बाद भी जारी रहेगी।

हालाँकि यूजर 15 मार्च के बाद रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज के अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने बैंक खाते या वॉलेट में कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

यह सुझाव दिया जाता है कि यूजर पेमेंट पाने के लिए किसी दूसरे बैंक या वॉलेट के अकाउंट से जुड़ा एक नया क्यूआर कोड प्राप्त करें।

एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी को दी मंजूरी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को मल्टी-पार्टी के तहत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के एप्लिकेशन (टीपीएपी) के रूप में यूपीआई में भाग लेने की मंजूरी दे दी। एनपीसी ने चार बैंक (एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक) ओसीएल के लिए पीएसपी (भुगतान प्रणाली प्रदाता) बैंक के रूप में कार्य करेंगे।

एनपीसीआई के अनुसार यस बैंक ओसीएल के लिए मौजूदा और नए यूपीआई मर्चेंट के लिए अधिग्रहण बैंक के रूप में भी कार्य करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। वे निर्धारित तिथि के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा बैलेंस का उपयोग कर

सालाना आधार पर 11.9 फीसदी बढ़ा भारत का निर्यात, इस वित्त वर्ष में टूट सकते हैं पिछले सभी रिकॉर्ड

भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। यह फरवरी में सालाना आधार पर 11.9 फीसदी बढ़कर 41.4 अरब डॉलर हो गया। मौजूदा वित्त वर्ष के 11 महीनों में यह एक्सपोर्ट का सबसे उच्चतम स्तर है। आयात की बात करें तो भारत ने फरवरी में करीब 60.1 अरब डॉलर का सामान मंगवाया। आइए जानते हैं कि फरवरी में भारत ने किस चीज का सबसे अधिक निर्यात किया।

नई दिल्ली। भारत का निर्यात सालाना आधार पर 11.9 फीसदी बढ़कर फरवरी में 41.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2023-24 में देश के निर्यात का सबसे उच्च स्तर है। इस दौरान खासकर इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात में बड़ा उछाल आया। वाणिज्य मंत्रालय (commerce ministry) के डेटा के अनुसार, इस दौरान हमारा व्यापार घाटा 18.7 अरब डॉलर रहा। यह एक साल पहले 16.57 अरब डॉलर था। इसकी सबसे बड़ी वजह रही गोल्ड इंपोर्ट में भारी बढ़ोतरी। अगर आयात की बात करें, तो भारत ने फरवरी में करीब 60.1 अरब डॉलर का सामान मंगवाया।

कितनी बढ़कर आएगी मार्च की सैलरी, किन-किन भत्तों में होने वाला है इजाफा? जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (DR) और महंगाई भत्ता (DA) 4 प्रतिशत बढ़ाने का एलान किया था। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मिलेगा जो पहले 46 फीसदी था। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन-कौन से भत्ते बढ़ने वाले हैं और मार्च में उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने होली से पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई राहत (DR) और महंगाई भत्ता (DA) 4 प्रतिशत बढ़ाने का एलान किया था। इसका मतलब है कि केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मिलेगा।

इसका 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने वाला है। सरकारी खजाने पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का बोझ भी बढ़ेगा।

आइए जानते हैं कि केंद्र के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा कैसे मिलेगा?

बढ़ जाएंगे ये भत्ते

महंगाई भत्ते में चार फीसदी के इजाफे से ट्रांसपोर्ट, डेप्यूटेशन और कैंटीन भत्ता 25 फीसदी बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता दरें 1 जनवरी 2024 से उनके मूल वेतन की 50 फीसदी हो जाएगी, जो पहले 46 फीसदी थी। कौन-कौन से भत्ते बढ़ेंगे। हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी और ग्रेच्युटी सीलिंग जैसे चीजों में वृद्धि होगी।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

फर्ज कीजिए कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी बेसिक सैलरी 25,600 रुपये महीना है। ऐसे में पहले 46 फीसदी के हिसाब से आपका महंगाई भत्ता था 11,776 रुपये। महंगाई भत्ता अब 50 फीसदी होने से यह रकम 12,800 रुपये हो जाएगा यानी इसमें 1,024 रुपये का इजाफा होगा।

HRA में भी इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा होगा। अगर केंद्रीय कर्मचारी X, Y & Z कैटेगरी के शहरों/कस्बों में रहते हैं तो HRA क्रमशः 30, 20 और 10 फीसदी हो गया है। पहल से तुलना करें, तो इसमें क्रमशः 3, 2 और एक फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

मार्च में आएगा मोटा वेतन

केंद्र सरकार का यह फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। मतलब कि केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के वेतन में जनवरी, फरवरी का डीए एरियर भी मिलेगा। साथ ही, HRA वृद्धि और दूसरे अलाउंस जुड़कर आएंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में वेतन के तौर पर अच्छी खासी रकम मिलेगी।

पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई कटौती के बाद गिर गए तेल कंपिनयों के शेयर

भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। मई 2022 के बाद आज राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कीमतों में संशोधन किया गया है। पेट्रोल-डीजल की नई कीमतों के बाद आज तेल कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे IOC BPCL HPCL आज लाल निशान पर कारोबार कर रही है।

नई दिल्ली। शुकवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल-डीजल की नई दरें लागू हो गई हैं। मई 2022 के बाद पहली बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में संशोधन किया गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर।

फ्यूल प्राइस में हुई कटौती के बाद आज तेल कंपिनयों के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

बीएसई पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का शेयर 8.10 प्रतिशत गिरकर 459.60 रुपये पर आ गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के शेयर 6.80 प्रतिशत गिरकर 158.40 रुपये पर और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर 6.37 प्रतिशत गिरकर 570.20 रुपये पर आ गए।

राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपये प्रति लीटर होगी, जो पहले 96.72 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि डीजल की कीमत अब 89.62 रुपये के बजाय 87.62 रुपये प्रति लीटर होगी।

खबर लिखते वक्त सेंसेक्स 529 अंक या 0.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,568.28 पर कारोबार कर रहा था।

बीमा पॉलिसी, बैंक अकाउंट और शेयर मार्केट सबके लिए सिर्फ एक KYC, जानिए कैसे मुमकिन होने वाला है ये

अभी हमें बीमा बैंक या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए अलग-अलग केवाईसी करानी पड़ती है। इसमें काफी वक्त लगता है और पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन अब सरकार ऐसा नियम लाने की तैयारी कर रही है जिसमें आप किसी एक वित्तीय संस्था में केवाईसी कराने के बाद उसका लाभ दूसरे क्षेत्रों में भी ले सकेंगे। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवा रहे या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं, हर बार आपकी नए सिरे से KYC (Know Your Customer) होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो भी KYC करानी पड़ती है। इसमें काफी वक्त जाया होता है।

अगर आप भी बार-बार KYC कराने की परेशानी से निजात चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार KYC से जुड़े नियम बदलकर यूनिफॉर्म केवाईसी (Uniform KYC) लागू करने पर विचार कर रही है। इसमें आपको एक ही बार विस्तृत KYC करानी पड़ेगी और फिर आप उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं।

आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म केवाईसी क्या है, इसका प्रस्ताव किसने दिया है और यह कब तक लागू हो सकती है।

यूनिफॉर्म KYC काम कैसे करता है?

यूनिफॉर्म केवाईसी में 14 अंकों का CKYC नंबर जारी होगा। इसका इस्तेमाल RBI, सेबी और इरडा जैसे रेगुलेटर के दायरे में आने वाली संस्थाओं में किया जा सकेगा। मतलब कि आपको बैंक अकाउंट, फास्टैग, शेयर बाजार और इंश्योरेंस के लिए नए सिरे से केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस CKYC नंबर देने भर से आपका काम हो जाएगा।

यूनिफॉर्म KYC का सुझाव कहां से मिला?

वित्त मंत्रालय ने साल 2016 में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) का गठन किया था। इसका मकसद था, जनता को बार-बार केवाईसी कराने की दिक्कतों से छुटकारा दिलाना था। यहीं से यूनिफॉर्म KYC का प्रस्ताव रखा गया।

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ग्राहकों के सत्यापन के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी (Uniform KYC) किया जा सकता है। इससे लोगों को केवाईसी के बार-बार मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) का मानना है कि बार-बार केवाईसी कराने की प्रक्रिया काफी थकाऊ है। अगर यूनिफॉर्म केवाईसी लागू किया जाता है, तो वक्त के साथ खर्च भी बचेगा। फिर जनता किसी वित्तीय संस्थान में एक बार केवाईसी कराने के बाद दूसरे सेगमेंट में भी उसका लाभ ले सकती है।

आईपीओ लिस्टिंग से हुए मुनाफे पर देना होता है टैक्स, जानें क्या है आयकर नियम

Tax on IPO Profit हम जो भी निवेश करते हैं उन सब की जानकारी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स लगता है। क्या इसमें करदाता को टैक्स कटौती का लाभ मिलता है या नहीं।

नई दिल्ली। कई निवेशकों को कंपनी के आईपीओ (IPO) के जरिये मुनाफा होता है। अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, आईपीओ लिस्टिंग पर निवेशकों को जो मुनाफा होता है उस पर उन्हें टैक्स (Tax) देना होता है। शेयर बाजार में जब निवेशक अपने शेयर बेचता है तो उस शेयर से हुए प्रॉफिट पर उन्हें टैक्स देना होता है।

कितना देना होता है टैक्स : निवेशक को आईपीओ अलॉट होने के बाद शेयर बेचने पर उतना ही टैक्स देना होता है जो किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर से कमाई पर लगता है। अगर निवेशक एक साल से कम अवधि में शेयर बेचता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Short Term Capital Gain Tax) देना होता है।

बेहाल मार्केट में भी 130 पर लिस्ट हुआ 83 रुपये का शेयर, अपर सर्किट के बाद निवेशक मालामाल

पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग (Pune E-Stock Broking) के आईपीओ ने शेयर बाजार में लिस्टिंग पर अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। आईपीओ में इसके शेयर 83 रुपये के भाव पर जारी हुए थे। लेकिन इसकी लिस्टिंग 130 रुपये पर हुई और फिर यह अपर सर्किट लगने के साथ 136.5 रुपये पर पहुंच गया। आइए इस शेयर और रिटर्न के बारे में सबकुछ जानते हैं।

नई दिल्ली। कॉर्पोरेट ब्रोकिंग हाउस पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग (Pune E-Stock Broking) ने शेयर बाजार में लिस्टिंग पर अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। आईपीओ में इसके शेयर 83 रुपये के भाव पर जारी हुए। लेकिन, BSE स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) पर 130 रुपये की लिस्टिंग के साथ इसने जोरदार एंट्री की है।

इसका मतलब है कि पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग ने लिस्टिंग पर आईपीओ निवेशकों को तकरीबन 57 फीसदी का मुनाफा दिया है। एक ओर जहां ओवरऑल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई, वहीं ई-स्टॉक ब्रोकिंग में लिस्टिंग के बाद भी तेजी दिखी। यह अपर सर्किट के साथ 136.50 पर पहुंच गया है। मतलब कि अब निवेशकों का मुनाफा 64 फीसदी से अधिक हो गया है। सिर्फ एक ही दिन में इसने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

आईपीओ को मिला था शानदार रिस्पॉन्स

पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग का 38.23 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 12 मार्च को बंद हुआ। प्राइस बैंड 78 से 83 रुपये था। इसे निवेशकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और यह 371.16 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस आईपीओ में 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 46,06,400 नए शेयर जारी हुए हैं। कंपनी आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और आईपीओ से जुड़े खर्चों को भरने में करेगी।

क्या करती है पुणे ई-स्टॉक ब्रोकिंग?

पुणे ई-स्टॉक ब्रोकरेज लिमिटेड एक कॉर्पोरेट ब्रोकरेज है, जो अपने कस्टमर को स्टॉक एक्सचेंज के साथ इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटीज के बिजनेस के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। अगर मालिकाना हक की बात करें, तो इसके प्रमोटर संदीप सुंदरलाल शाह, परेश सुंदरलाल शाह, दैदिप्य घोडनादिकर, वृजेश नवनीतभाई शाह, देवेंद्र रामचंद्र घोडनादिकर और वृजेश कृष्णकुमार शाह हैं।

पेटीएम को मिला चार बैंकों का साथ,15 मार्च के बाद भी शुरु रहेगी यूपीआई पेमेंट

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। पेटीएम को मिला चार बैंकों का साथ,15 मार्च के बाद अब यूपीआई पेमेंट पर नो टेंशन, पेटीएम के पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के रूप में चार बैंक- एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, यस बैंक काम करेंगे।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को मल्टी-बैंक मॉडल के तहत यूपीआई सिस्टम में थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के रूप में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई ने बताया कि यस बैंक, पेटीएम लेनदेन को मौजूदा, नए यूपीआई मर्चेंट्स के लिए मर्चेंट अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करेगा।

क्या कहा एनपीसीआई ने

एनपीसीआई ने कहा- यह इंतजाम पेटीएम के मौजूदा यूजर्स और मर्चेंट्स को यूपीआई लेनदेन, स्वतःभुगतान (ऑटोपे) की सहमति को निर्बाध ढंग से जारी रखने में सक्षम बनाएगा। वहीं, पेटीएम को सलाह दी गई है कि जहां भी जरूरी हो, सभी मौजूदा हैंडल और सहमतियों को जल्द-से-जल्द नए भुगतान प्रणाली प्रदाता बैंकों में स्थानांतरित कर लें।

एनपीसीआई का यह फैसला रिजर्व बैंक की उस समयसीमा से एक दिन पहले आया है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों और कारोबारियों को 15 मार्च तक अपने खाते अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। बता दें कि 17 फरवरी को पेटीएम ने भी अपने नोडल खातों को एक्सिस बैंक के साथ स्थानांतरित कर दिया था।

आरबीआई ने मदद करने की दी थी सलाह

बीते दिनों केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद करने को कहा था। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित हैंडल का उपयोग करके यूपीआई ग्राहकों को बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एनपीसीआई से 'थर्ड पार्टी ऐप' प्रोवाइडर बनने की संभावना तलाशने को कहा था।

15 मार्च के बाद क्या-क्या चलता रहेगा

यूजर्स और व्यापारियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पेटीएम ऐप काम कर रहा है और 15 मार्च 2024 के बाद भी ये काम करना जारी रखेगा। उदाहरण के लिए पेटीएम क्यूआर कोड, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीनें भी पूरी तरह चालू रहेंगी। इसी तरह, पेटीएम ऐप पर फिल्मों, इवेंट, यात्रा (मेट्रो, फ्लाइट, ट्रेन, बस) की टिकट बुकिंग सहित अन्य सभी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। यूजर्स अपने मोबाइल फोन, डीटीएच या ओटीटी सब्सक्रिप्शन को रिचार्ज करना जारी रख सकते हैं और सभी यूटिलिटी बिलों (बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट) का भुगतान पेटीएम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।

लोकसभा प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज (16 मार्च) लेंगे भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबन्धन समिति एवं कोर कमेटी की बैठक

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाडा। भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबन्धन समिति एवं कोर कमेटी की बैठक आज दिनांक 16 मार्च को राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री एवं भीलवाड़ा लोकसभा प्रभारी हीरालाल नागर के मुख्य आतिथ्य, सांसद सुभाष बहेड़िया के सानिध्य एवं जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय पर प्रातः 11.30 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ भीलवाड़ा लोकसभा की सभी विधानसभाओं में पार्टी की स्थिति की समीक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। इससे पूर्व जिला कार्यालय पर ही भीलवाड़ा लोकसभा के सभी विधानसभा प्रभारियों, विधानसभा संयोजकों एवं विधानसभा विस्तारकों की भी बैठक आयोजित होगी। दोनों ही बैठकें आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अतिमहत्वपूर्ण रहेगी।

भारतीय सफाई सेवक संघ के चेयरमैन कमल नाहर ने चीफ सेंटरी इस्पेक्टर एसोसिएशन के नव नियुक्त प्रधान बने तजिंदर कुमार व उनकी टीम को पावन वाल्मीकि तीर्थ का चित्र भेंट कर सम्मानित किया।

अमृतसर (साहिल बेरी) पत्रकारों से बातचीत करते कमल कमल नाहर ने कहा कि सफाई सेवक व सेंट्री इंस्पेक्टर सेहत विभाग में शहर को साफ सुथरा बनाने में दोनों अहम भूमिका नभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सफाई सेवक संघ बिना मत भेद नगर निगम के अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारीयो की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। नव नियुक्त प्रधान तजिंदर कुमार ने कहां कि अगर किसी सफाई कर्मचारी को कोई मुश्किल आती है तो वह मिल बैठकर सुलझा लेगे, उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की मुश्किलों को एसोसिएशन पहल के आधार पर हल करने के लिए वचनबद्ध रहेगी। इस दौरान चीफ सेंटरी इंस्पेक्टर मलकीत सिंह खैरा, यूनियन प्रधान गोपी खोसला, रवि सभरवाल, दलबीर पेंडू, जज सिंह, नीटू, अनिल कुमार, दीपक, रिंकू, तरसेम लाल आदि सफाई कर्मचारियों ने एसोसिएशन के उप प्रधान राजन केसर, महासचिव हरिंदर पाल सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव दीवान, सतनाम सिंह चीफ सेंटरी इंस्पेक्टर साहिल मल्होत्रा को भी सिरोंपे व फूलों के गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया गया।

एक शाम गौ माता के नाम से जागरण और सर्व समाज प्रवासी स्नेह मिलन समारोह

तेलंगाना। हैदराबाद श्री आईजी गौशाला बालाजी नगर में एक शाम गौमाता के नाम जागरण आयोजित किया जारा है और राजस्थान पाली लोकसभा क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी बनने के पिला चावल देने के उपरांत हैदराबाद की पावन धरा आगमन पर समस्त सर्व समाज राजस्थानी से भव्य स्वागत किया जाएगा। शाम 6बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर पीपी चौधरी का सम्मान किया जाएगा। निवेदक आखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना अध्यक्ष हजारीराम काग, सचिव सोहनलाल हाम्बड़, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंत्री एव कोरेमुला बडेर अध्यक्ष कालुराम काग उपस्थित रहेगे।

जिस देश का है छोटा संविधान वहा कोई भी अपराधी सजा से नही बचता है और भारत देश जहां सबसे भारी भरकम संविधान है कोई अपराधी फंसता नहीं है

परिवहन विशेष न्यूज

सरकारी राशन की दुकान पर भीड़ देखिये, हाथ में 20,000 का मोबाइल लेकर 70,000 की बाइक पर बैठकर 2 रुपये किलो चावल लेने आते है गरीब लोग।

दिल्ली में बस सफर फ्री करने वाली महिलाओं के हाथ में हाथ मे 50,000 का फोन और चेहरे पर 10,000 का चश्मा देखने को आम मिलता है

जिस देश में नसबन्दी कराने वाले को सिर्फ़ 1500₹ और बच्चा पैदा करने पर 6000₹ मिलते हों वहा कैसा जनसंख्या नियंत्रण ?

एक बादशाह ने गधों को क़तार में चलता देखा तो धोबी से पूछा, ₹यह कैसे सीधे चलते है..?₹ धोबी ने जवाब दिया, ₹जो लाइन तोड़ता है उसे मैं सज़ा देता हूँ, बस इसलिये ये सीधे चलते हैं।₹ बादशाह बोला, ₹मेरे मुल्क में अमन क़ायम कर सकते हो..?₹

धोबी ने हामी भर ली। धोबी शहर आया तो बादशाह ने उसे मुन्सिफ बना दिया, और एक चोर का मुक़दमा आ गया, धोबी ने कहा चोर का हाथ काट दो। जल्लाद ने वज़ीर की तरफ देखा और धोबी के कान में बोला, ₹ये वज़ीर साहब का ख़ास आदमी है।₹ धोबी ने दोबारा कहा इसका हाथ काट दो, तो वज़ीर ने सरगोशी की कि ये अपना आदमी है ख़याल करो। इस बार धोबी ने कहा, ₹चोर का हाथ और वज़ीर की ज़ुबान दोनों काट दो, और एक फैसले से ही मुल्क में अमन क़ायम हो गया...।

बिलकुल इसी न्याय की जरुरत हमारे देश को है।

उदाहरण के लिए आप जाने देश में जन प्रतिनिधियों, जन नेताओं, सरपंच एवम्जनता द्वारा अपने वोट की ताकत से अपने हित के लिए नियुक्त करवाए हुए नेताओं / जन प्रतिनिधियों की सैलरी जरुरत की पूर्ति हेतु होती है पर आज तक जनता की समझ में यह नहीं आ पाया है की मात्र 2 साल बाद ही स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कोठियां और महल कैसे खरीद लेते हैं और कहाँ से इनके पास आ जाता है इतना पैसा..... ?

यह लेख / कहानी भारत देश के सभी जनप्रतिनिधियो को समर्पित है। भारत देश वासियों ग़ौर करके सोचना जो व्यक्ति सेना के जवानो, देश की पुलिस, शासन- प्रशासन और देश के क़ानून से भी नही डरते वह आप और हम जैसे निशस्त्र लोगों से डरेंगे क्या... ????

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

प्रसिद्ध समाजसेवी, युवा नेता एवं राजनीतिज्ञ डॉ.राजीव मिश्रा सांसद प्रत्याशी गौतमबुद्ध नगर लोकसभा ने कैंप कार्यालय खोले

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। जयहिंद नेशनल पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.राजीव मिश्रा को गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सांसद प्रत्याशी घोषित होने के पश्चात अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है1

डॉ. राजीव मिश्रा ने अपने पांचों विधानसभाओं नोयडा, दादरी, सिकंदराबाद, जेवर एवं खुर्जा में कार्यालयों का उदघाटन, माननीय अध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव जी के कर कामलो द्वारा कराया।

डॉ.आशीष श्रीवास्तव (राष्ट्रीय अध्यक्ष) जयहिंद नेशनल पार्टी के गरिमामई उपस्थिति में यह सफल आयोजन हुआ। अध्यक्ष जी का स्वागत माल्यार्पण और शॉल ओढ़ा कर डॉ.राजीव मिश्रा ने किया।

अध्यक्ष जी ने डॉ राजीव मिश्रा जी को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉ. आशीष श्रीवास्तव जी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी एक नए विचार धारा से आगे बढ़ रही है और देश में आज भी व्याप्त कुरीतिओं को एक एक करके ख़त्म करने का काम करेगी। आज भी देश में राष्ट्रीय पार्टीयाँ वही 72 वर्ष पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है,और देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है।जयहिंद नेशनल पार्टी प्रतिमान बदलाव लाने का काम कर रही है और इसके पूर्ण होने तक करती रहेगी।उन्होंने यह भी पुरज़ोर से कहा कि अब देश की राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं और सभी क्षेत्र के भलें लोगों को अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

सांसद प्रत्याशी डॉ.राजीव मिश्रा जी ने सभी का स्वागत किया और अपने संबोधन में सभी को विश्वास दिलाया कि वह जनता के भरोसे पर खरे उतरने का प्रतिदिन काम करेंगे।

डॉ. राजीव ने यहाँ के वर्तमान सांसद को खुले मंच पर जनता के सामने अपने प्रश्नों के उत्तर देने का आग्रह किया 1जो उन्हें जनता के समक्ष जा कर जानकारी हुई1

उन्होंने किसी भी प्रमुख मीडिया मंच पर पिछले दो बार के गौतमबुद्ध नगर लोकसभा के सांसद को प्रमुख लोकल मुद्दों पर अपने साथ बहस करने का आह्वान किया।

पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ और सभी ने शपथ ली कि वह अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद रहे डॉ.हिमांशु भटनागर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मेरठ लोकसभा सांसद प्रत्याशी, श्री प्रिंस श्रीवास्तव, अध्यक्ष ,चुनाव समिति, श्री रणजीत मिश्रा ,श्री अजीत दीक्षित, श्री आदित्य सक्सेना, श्री रामेन्द्र दीक्षित, श्री अभिनंदन मिश्रा, महेश रत्नाकर, श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव, ठाकुर युवराज सिंह, डॉ.अखिलेन्द्र खरे, डॉ.विष्णु मोहन श्रीवास्तव, डॉ.फ़ैज, डॉ.शैलेंद्र सरोज, अंकित अग्रवाल, राजन यादव, नरेश राणा, मस्तराम यादव, अनुराग पांडेय, विजेन्द्र यादव, सुनील यादव, किशन राजपूत, सुनील कुमार, अंश मिश्रा, स्तुति, सैफी खान, आर. वी. सिंह एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा 25टी बोलार्ड पुल टग लॉन्च किया

परिवहन विशेष न्यूज

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) ने भारतीय नौसेना के लिए अपना दूसरा 25टी बोलार्ड पुल टग 'बाहुबली' लॉन्च किया है। जहाज को बैरकपुर के टीटागढ़ स्थित कंपनी की फेसिलिटी में बनाया गया है। यह लॉन्च रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के तहत नवंबर, 2021 में भारतीय नौसेना से कंपनी द्वारा प्राप्त छह 25 बीपी टग्स ऑर्डर का हिस्सा है। लॉन्च के बाद चौथे 25टी बोलार्ड पुल टग, युवान (यार्ड 338) के लिए कील बिछाने का समारोह भी आयोजित किया गया।

एसएसबी (कोलकाता) के प्रेसिडेंट कमोडोर अतुल मैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लॉन्च समारोह में कमोडोर एस. श्रीकुमार, वारशिप प्रोडक्शन सुप्रिन्टेन्डेंट (कोलकाता) सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति देखी गई। टीटागढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले कमोडोर संजय देशपांडे (सेवानिवृत्त), कार्यकारी निदेशक (ओपीएस), गौतम रॉय, कार्यकारी निदेशक और कमोडोर ईशान टंडन (सेवानिवृत्त), वीपी-एसबीडी थे।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री उमेश चौधरी ने एक बयान में कहा, ''टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड में यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है; इस साल की शुरुआत में पहला टग लॉन्च करने के बाद, हमने रिकॉर्ड समय में दूसरा टग लॉन्च किया है, जो कि पहला टग लॉन्च करने के सिर्फ 2 महीने के भीतर संभव कर दिखाया है। यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। हम निर्धारित की गई समयसीमा को पूरा करने के लिए शेष जहाजों के साथ पूरे परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं।''

'कांग्रेस जीती 500 रुपए में गैस, 3000 में क्विंटल चावल'

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: प्रदेश कांग्रेस ने आज अपने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने जहां 'मोदी गारंटी' दी है, वहीं कांग्रेस ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है और इसे 'कांग्रेस गारंटी' बताकर 10 गारंटी लॉन्च की है। फोकस महिलाओं, किसानों, युवा महिलाओं, एसएचजी पर है। कांग्रेस ने प्रति परिवार मुखिया महिला भत्ता 2,000 रुपये, वृद्धावस्था, विधवाओं, गरीबों के लिए 2,000 रुपये मासिक भत्ता, बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये और किसानों के लिए 2,000 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया है। पार्टी ने अपने गारंटी पत्र में सरकारी कर्मचारियों समेत सभी को 25 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का जिक्र किया है। साफ है कि कांग्रेस ने चिटफंड घाटे वालों को 6 महीने में पैसा लौटाने का वादा किया है।

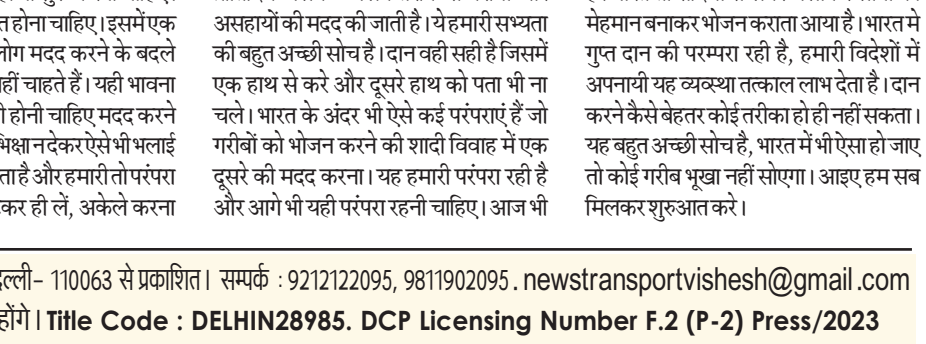

हमारी वर्षो पुरानी गुप्तदान की परम्परा को आजकल "ससपेंशन" नाम से अपना रहें विदेशी : वरिष्ठ समाजसेवी अरविन्द पुष्कर एडवोकेट

परिवहन विशेष न्यूज

अपील - आइएं मिलकर एक कदम ससपेंशन की ओर हम भी बढ़ाएं : वरिष्ठ समाजसेवी अरविन्द पुष्कर एडवोकेट

आगरा। भारत में सदैव लाचार, गरीब, जरुरतमंदों और बेसहारा की हमेशा मदद की जाती है और अलग-अलग प्रकार से खाने के प्रबंध किए जाते हैं। आज हमारी इन्ही शानदार परम्परा को यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ससपेंशन नाम से अपनाया जा रहा हैं। विदेशी हमारी संस्कृती की अच्छी सोच को बढ़ाते हुए वहां जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर सराहनीय कार्य कर रहें हैं।

इस सन्दर्भ में राष्ट्रवादी सामाजिक चिंतक एवं वरिष्ठ समाजसेवी अरविन्द पुष्कर एडवोकेट ने कहा कि भारतवर्ष सच्ची मानवता के मसीहाओं और दानवीरों की भूमि रही हैं, हमारी सभ्यता में तो ऐसा सदियों से होता आया है। ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात हैं कि हमारी सदियों पुरानी सभ्यता को विदेशों में ससपेंशन नाम से अपनाया जा रहा हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूरोप और अमेरिका में सहित कई शहरों में आजकल आमतौर पर एक दृश्य देखा जाता है कि एक रेस्तरां है। उसके कैश काउंटर पर एक लोग आते हैं और कहते हैं कि - 5 कॉफ़ी, 1 ससपेंशन फिर वह पांच कॉफी के पैसे दे देते है और चार कप कॉफी ले जाते है। थोड़ी देर बाद, एक और आदमी आता है और कहता है कि 4 लंच 2 ससपेंशन वह चार लंच का भुगतान करता है और दो लंच पैकेट्स ले जाता है। फिर एक और आता है आर्डर देता है 10 कॉफ़ी, 6 ससपेंशन वह दस के लिए भुगतान करता है, चार कॉफी ले जाता है, फिर थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जर्जर कपड़ों में काउंटर पर आकर पूछता है- एनी ससपेंडेड कॉफ़ी ? काउंटर पर मौजूद व्यक्ति उनसे कहता हैं हाँ, और एक कप गर्म कॉफी उसको दे देती है। कुछ देर बाद वैसे ही एक और दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी अंदर आता है और पूछता है कि एनी ससपेंडेड लंच ? तो काउंटर पर मौजूद व्यक्ति गर्म खाने का एक पार्सल और पानी की एक बोतल उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है और यह क्रम अधिक पेमेंट करने वाले दानदाताओं और बिना पेमेंट खान-पान ले जाने वाले बुजुर्ग जरूरतमंदों का दिन भर चलता रहता है। यानी अपनी पहचान न कराते हुए और किसी के चेहरे को जाने बिना भी अज्ञात गरीबों, जरुरतमन्दों की मदद करना विदेशी नागरिकों की कल्चर बन गया हैं और यह कल्चर अब यूरोप के अन्य कई देशों में आजकल बहुत तेजी से फैल रहा हैं लेकिन हमारे भारत में यूरोप से भी पहले से यह परंपरा चल रही है। ये अलग बात है की हम आप अपने देश में नहीं देख पाये, यूरोप वाले हमारे देश से ही सीखकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी संस्कृती हैं, यह बहुत अच्छी परंपरा है कि जाहिर किये बगैर किसी भूखे को खाना खिला देना बहुत ही सुन्दर पद्धति का अति उत्तम विधान है। इसे एक अच्छी सोच के साथ यहां भी शुरू करनी चाहिए। अच्छे विचार का स्वागत होना चाहिए। इसमें एक बात अच्छी लगी कि लोग मदद करने के बदले अपने नाम का प्रचार नहीं चाहते हैं। यही भावना अपने देशवासियों में भी होनी चाहिए मदद करने का तरीका कुछ भी हो, भिक्षा न देकर ऐसे भी भलाई का काम किया जा सकता है और हमारी तो परंपरा है कि भोजन पानी बांटकर ही लें, अकेले करना अशोभनीय है, जब भी भुखा प्यासा जरूरतमंद मिले उसे भोजन पानी देना चाहिए।

श्री पुष्कर ने आगे कहा कि भारत में भी खान-पान की "ससपेंशन" जैसी प्रथा प्रारंभ हो सकती है क्योंकि हमारी संस्कृती से संस्कार ही ऐसे होते हैं। यही सत्य है। ये दान का महत्व ही है कि जब एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। इसी अच्छी पहल कहीं भी हो अपनाना चाहिए। भंडारे हो या लंगर नाम सिर्फ भाषा के कारण अलग हो सकते हैं। मानवता की सेवा सर्वोपरि है। इसीलिए यहां प्रीतिदिन अलग - अलग तरीके से गरीबों और असहायों की मदद की जाती है। ये हमारी सभ्यता की बहुत अच्छी सोच है। दान वही सही है जिसमें एक हाथ से करे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। भारत के अंदर भी ऐसे कई परंपराएं हैं जो गरीबों को भोजन करने की शादी विवाह में एक दूसरे की मदद करना। यह हमारी परंपरा रही है और आगे भी यही परंपरा रहनी चाहिए। आज भी हमारे देश में कई स्थानों पर बिना किसी को बताए सद्कर्म कर रहे हैं। भारत में पहले भी थी ये प्रथा और अब भी है। इसे गुप्तदान कहा जाता ही है। बस ये विदेशों में "ससपेंशन" नाम से बताया जाता हैं और भारत में छुपाया जाता है। भारत में जो है, वो पूरी दुनियां में नहीं है। हमारी सभ्यता में प्रसाद, लंगर, भंडारा और दान पुण्य हर जगह हैं। इसीलिए आजकल पूरी दुनियां के लोग हमारी सभ्यता अपना रहें हैं क्योंकि भारत में हर जीव को खिलाया जाता है। क्योंकि पुंण्य मुश्किल से मिलता है, परन्तु इसे करने में बड़ा सुकून मिलता है। भारत तो सदियों से लंगर चलाकर लोगों को मेहमान बनाकर भोजन कराता आया है। भारत मे गुप्त दान की परम्परा रही है, हमारी विदेशों में अपनायी यह व्यवस्था तत्काल लाभ देता है। दान करने कैसे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यह बहुत अच्छी सोच है, भारत में भी ऐसा हो जाए तो कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। आइए हम सब मिलकर शुरुआत करे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023